

मोसर बेयर करमचारी यूनियन टीएचआर। राष्ट्रपति

महेश चंद शर्मा

बी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2019 की लिखित याचिका (सी) संख्या 421)

02 मई, 2023

[एम. आर. शाह और संजीव खन्ना, जे. जे.]

कंपनी अधिनियम, 2013: एस. 327 (7) - संवैधानिक वैधता

-

आयोजित किया गया: एस. 327 (7) वह एस. एस. प्रदान करता है। 326 और 327 आई. बी. सी. के तहत परिसमापन की स्थिति में लागू नहीं होगा।

आई. बी. सी. और यह कंपनी के परिसमापन के संबंध में लागू होता है।

आई. बी. सी. के तहत, इस प्रकार, एस। 327 (7) इसे मनमाना और/या कला का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है। 21- किसी कंपनी के परिसमापन के मामले में

आई. बी. सी., एस के प्रावधान। 53 आई. बी. सी. और आई. बी. सी. के अन्य प्रावधान लागू होंगे क्योंकि कंपनी को आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत परिसमापन या समाप्त करने का आदेश दिया जाता है- परिसंपत्तियों का वितरण एस के अनुसार किया जाना चाहिए। 53 आई. बी. सी. एस के अधीन। 36 (4) आई. बी. सी.-एस के अनुसार। 53 (1) (ख) परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले चौबीस महीने की अवधि के लिए श्रमिकों का बकाया श्रेणीबद्ध होगा।

इस तरह के सुरक्षित लेनदार द्वारा प्रतिभूति छोड़ने की स्थिति में श्रमिकों और सुरक्षित लेनदार के बीच समान रूप से-इस प्रकार, इसे मनमाना और कला का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है। 21 - दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-ss. 53 और 36 (4)।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016: एस. 53 - - झरना।

के तहत तंत्र-आयोजित: जलप्रपात तंत्र एक संरचित गणितीय सूत्र पर आधारित है, और पदानुक्रम कई योग्यताओं के साथ प्राथमिकता के क्रम में ऋणों के भुगतान के संदर्भ में बनाया जाता है, किसी भी प्रावधान को कम करने या जलप्रपात तंत्र में पदानुक्रम को फिर से व्यवस्थित करने से कई यात्राएं हो सकती हैं और समग्र रूप से संतुलन के काम में बाधा आ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अस्थिरता पैदा हो सकती है- जलप्रपात तंत्र में हर बदलाव से सुरक्षित लेनदारों, परिचालन लेनदारों और यहां तक कि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों और हितों के संतुलन पर व्यापक प्रभाव पड़ना तय है-जलप्रपात तंत्र में, दिवाला

समाधान प्रक्रिया और परिसमापन की लागत के बाद, सुरक्षित लेनदार सबसे अधिक प्राथमिकता साझा करते हैं।

[2023] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्रमिकों के बकाया की एक परिभाषित अवधि-श्रमिकों के अवैतनिक बकाया को संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के अनुरूप और धाराओं द्वारा निर्धारित जलप्रपात तंत्र के संदर्भ में पर्याप्त और महत्वपूर्ण रूप से संरक्षित किया जाता है। 53 .

रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1.1 दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 और आई. बी. सी. की धारा 53 के अधिनियमन को ध्यान में रखते हुए, यह

अधिनियम, 2013 में संशोधन की आवश्यकता है। धारा 327 की उप-धारा (7) के अनुसार, आई. बी. सी. के तहत परिसमापन की स्थिति में धारा 326 और 327 लागू नहीं होंगी। अधिनियम, 2013 में संशोधन करने और आई. बी. सी. के तहत परिसमापन की स्थिति में धारा 326 और 327 को बाहर करने का उद्देश्य और उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि किसी कंपनी के परिसमापन के संबंध में दो अलग-अलग प्रावधान नहीं हो सकते हैं। इसलिए, के अधिनियम को ध्यान में रखते हुए

आई. बी. सी. ने अधिनियम, 2013 की धारा 326 और 327 की प्रयोज्यता को बाहर करना आवश्यक बना दिया, जिसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 6] [111-ई-एफ]

1.2 . धारा 327 की उप-धारा (7) आई. बी. सी. के तहत किसी कंपनी के परिसमापन के मामले में लागू होगी। के मामले में आई. बी. सी. के तहत किसी कंपनी का परिसमापन, धारा 53 के प्रावधान

आई. बी. सी. और आई. बी. सी. के अन्य प्रावधान लागू होंगे क्योंकि आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत कंपनी को समाप्त या समाप्त करने का आदेश दिया जाता है। इसलिए, केवल इसलिए कि पहले के तहत

शासन और कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत किसी कंपनी को बंद करने के मामले में, श्रमिकों के बकाया में सुरक्षित लेनदार के बराबर राशि हो सकती है, याचिकाकर्ता आईबीसी के तहत कंपनी को बंद करने/परिसमापन के मामले में समान लाभ का दावा नहीं कर सकता है। दलों द्वारा शासित किया जाएगा

आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत किसी कंपनी के परिसमापन के मामले में आई. बी. सी. के प्रावधान। [पैरा 6.1] [111-जी-एच; 112-ए-बी]

1.3 . आई. बी. सी. की धारा 53 आई. बी. सी. के तहत किसी कंपनी के परिसमापन के मामले में परिसंपत्तियों के वितरण का प्रावधान करती है। के अनुसार

धारा 53 (1) (बी) परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले चौबीस महीने की अवधि के लिए श्रमिकों के बकाया को श्रमिकों और सुरक्षित लेनदार के बीच समान रूप से रैंक किया जाएगा, यदि ऐसे सुरक्षित लेनदार ने मोसर बेयर कर्मचारी संघ में प्रतिभूति छोड़ दी है।

परिसमापन शुरू होने की तारीख के बीच समान रूप से रैंक होगी उक्त सीमा तक श्रमिकों का
बकाया और सुरक्षित लेनदार का बकाया। इसलिए, इसे मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का
उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 6.2] [112 बी-एफ]

अधिनियम की तुलना में, 1956/2013। आई. बी. सी. एक नया दिवाला तंत्र है, इसलिए आई. बी. सी. के तहत प्रावधानों की तुलना पिछली व्यवस्था, अर्थात् कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के साथ नहीं की जा सकती है। [पैरा 6.2] [112-एफ]

ऋणों का भुगतान करें, और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 271 के खंड (डी) का भुगतान करें, जब किसी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XIX के तहत बंद करने का निर्देश दिया जाता है। वास्तव में, कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XIX को 15 नवंबर 2016 से 2016 के अधिनियम संख्या 31 और संहिता की ग्यारहवीं अनुसूची के संदर्भ में हटा दिया गया था। संहिता, जैसा कि अधिनियमित किया गया है, विशेष रूप से संबंधित और व्यवहार करने वाला एक अलग और समेकित अधिनियम है। उन कंपनियों के साथ जो दिवालिया हैं और बकाया का भुगतान करने में असमर्थ हैं, और पहले कंपनी के पुनर्वास और पुनरुद्धार की संभावना का पता लगाने के लिए एक जनादेश के साथ एक प्रक्रिया की परिकल्पना करती हैं, और अंतिम कॉल के रूप में विघटन/समापन। यह महत्वपूर्ण है और दिवालियापन के लिए तत्कालीन मौजूदा ढांचे और [2023] 6 एस. सी. आर. को पूरी तरह से बदल देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आयोगों और विशेषज्ञों, एक मामले में जो संबंधित है पूरे देश की अर्थव्यवस्था। [पैरा 7.2,7.3]
[115-ए-ई]

1.6 श्रमिकों के बकाया के संदर्भ में संहिता में अब निर्धारित झरना तंत्र एक सुविचारित और विचारशील निर्णय है। वाटरफॉल मैकेनिज्म और श्रमिकों के बकाया के लिए निर्धारित पदानुक्रम को संहिता के समग्र उद्देश्य में देखा जाना चाहिए, जो यह पता लगाने के लिए है कि क्या कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित किया जा सकता है ताकि नौकरी न जाए, आर्थिक संपत्तियों का उपयोग अधिकतम हो और एक प्रभावी कानूनी ढांचा हो।

जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों के हाथों में ऋण की व्यवहार्यता को बढ़ाता है। संहिता वित्तीय प्रभाव को पहचानती है सुरक्षित लेनदारों या सार्वजनिक धन से निपटने वाले वित्तीय संस्थानों पर, क्योंकि उनका आर्थिक स्वास्थ्य आम जनता के साथ-साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तक उद्योग में आर्थिक विकास और नए निवेश नहीं होते,

रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे, जो

आर्थिक संकट, दिवालियापन और दिवालियापन की ओर ले जाता है। ये सभी जटिल आर्थिक मामले हैं जिनमें विभिन्न परस्पर विरोधी मामले हैं। हितों को संतुलित और एक के बजाय समग्र होना चाहिए।

एक तरफा, दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। प्रत्येक राय में योग्यता हो सकती है, लेकिन न्यायालय शायद ही विधायिका के लिए अपने स्वयं के विवेक या दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित कर सकता है, विशेष रूप से जब अधिनियम अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली जटिल वित्तीय और वाणिज्यिक चुनौतियों पर एक विचारशील और विवादास्पद समीक्षा का परिणाम है। [पैरा 8] [116-बी-एफ]

1.7 कंपनी अधिनियम, 2013 दिवालियापन और दिवालियापन से नहीं निपटता है जब कंपनियां अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होती हैं।

या कंपनियों के पुनरुद्धार और पुनर्वास से संबंधित पहलू और यदि पुनरुद्धार और पुनर्वास संभव नहीं है तो उनका समापन। सैद्धांतिक रूप से, इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि दिवालियापन और ऋण का भुगतान करने में असमर्थता के आधार पर कंपनी के पुनरुद्धार या समापन के मामले उन मामलों से अलग हैं जहां कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 के तहत बंद किया जाता है।

मोसर बेयर करमचारी यूनियन टीएचआर। राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनाम। भारत का संघ

स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और मनमाना, कानून को केवल इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जाएगा कि श्रमिकों द्वारा कुछ या मामूली बलिदान किया जाना है। प्रस्तुतिकरण अस्वीकार कर दिया जाता है कि पता लगाने के लिए चाहे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ हो या क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया गया था, इस न्यायालय को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिकल्पित झरना तंत्र की शब्दशः जांच करनी चाहिए, जहां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 271 के आधार (ए) से (ई) के संदर्भ में कंपनी को समाप्त कर दिया गया है; और जब दिवालिया कंपनी को संहिता के तहत पुनर्जीवित, पुनर्वास या समाप्त करने की मांग की जाती है तो श्रमिकों के अधिकारों की। दोनों के उद्देश्य और उद्देश्य के संदर्भ में आधार और परिस्थितियाँ

अधिनियम पूरी तरह से अलग हैं। [पैरा 9] [123-ए-जी]

1.8 संहिता की धारा 53 जो एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होती है और कहती है कि इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद

संसद या तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी विधि में निहित परिसमापन परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय को प्राथमिकता के क्रम में, जो निर्धारित है, और ऐसी अवधि और ऐसी रीति के भीतर वितरित किया जाएगा जो विनिर्दिष्ट की जाए। संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) का परिणाम यह है कि यह इन अधिकारों पर हावी हो जाएगा - पक्षकार, जिसमें सुरक्षित लेनदार भी शामिल है, जब उक्त प्रावधान लागू होता है। संहिता की धारा 53 पूर्ण और

व्यापक संहिता जो परिसंपत्तियों का संग्रह सुनिश्चित करती है और फिर

लेनदारों को भुगतान करने का तरीका प्रदान करता है।

तक कि [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.9 धारा 53 की उप-धारा (1) का खंड (ए) दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत और परिसमापन लागत से संबंधित है। जिनका पूरा भुगतान किया जाना है। उक्त खंड के संबंध में कोई शिकायत या मुद्दा नहीं उठाया जा सकता है। धारा 53 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में कहा गया है कि परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले चौबीस महीने की अवधि के लिए श्रमिकों के बकाया के रूप में देय ऋण और ऐसे सुरक्षित लेनदार द्वारा प्रतिभूति छोड़ने की स्थिति में सुरक्षित लेनदार को देय ऋण।

संहिता की धारा 52 में निर्धारित तरीका श्रमिकों और सुरक्षित लेनदारों के बीच और उनके बीच समान रूप से होगा। संहिता की धारा 53 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि 'श्रमिकों के बकाया' का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 में दिया गया है। दूसरे शब्दों में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 का स्पष्टीकरण शामिल किया गया है और संहिता की धारा 53 के खंड (बी) से उप-धारा (1) में निर्धारित झरने तंत्र पर लागू होता है। यहाँ जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि संहिता की धारा 53 के खंड (बी) से उप-धारा (1) के तहत, श्रमिकों का बकाया परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले चौबीस महीने की अवधि के लिए है। [पैरा 15.1] [131-ई-एच; 132-ए]

1.10 जलप्रपात तंत्र एक संरचित गणितीय सूत्र पर आधारित है, और पदानुक्रम कई योग्यताओं के साथ प्राथमिकता के क्रम में ऋणों के भुगतान के संदर्भ में बनाया गया है, किसी भी प्रावधान को समाप्त करना या प्रावधानों में से किसी एक को फिर से व्यवस्थित करना। जलप्रपात तंत्र में पदानुक्रम कई यात्राओं का कारण बन सकता है और समग्र रूप से संतुलन और ठहराव के काम को बाधित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अस्थिरता हो सकती है। झरने के तंत्र में हर बदलाव

यह सुरक्षित ऋणदाताओं, परिचालन ऋणदाताओं और यहां तक कि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों और हितों के संतुलन पर व्यापक प्रभाव डालने के लिए बाध्य है। तथ्यों के आधार पर,

कुछ मामलों में, संहिता में जलप्रपात तंत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 के तहत प्रदान किए गए पदानुक्रम की तुलना में अधिक फायदेमंद हो सकता है और इसके विपरीत। [पैरा 16] [132-जी-एच; 133 ए] मोसर बेयर करमचारी यूनियन टीएचआर।

राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनाम। भारत का संघ

1.11 . जलप्रपात तंत्र में, दिवाला समाधान प्रक्रिया और परिसमापन की लागत के बाद, सुरक्षित लेनदार

श्रमिकों के बकाया की एक निर्धारित अवधि के साथ उच्चतम प्राथमिकता को साझा करें। संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और संहिता की धारा 53 द्वारा निर्धारित झरना तंत्र के संदर्भ में श्रमिकों के अवैतनिक बकाया को पर्याप्त और महत्वपूर्ण रूप से संरक्षित किया जाता है। किसी भी मामले में

सुरक्षित लेनदार द्वारा प्रतिभूति का त्याग या गैर-त्याग, श्रमिकों के हितों को संहिता के तहत संरक्षित किया जाता है। वास्तव में, सुरक्षित लेनदार बड़े पैमाने पर ऋण ले रहे हैं और कर्मचारियों को संहिता की धारा 53 के अनुसार न्यायसंगत और उचित तरीके से न्यायसंगत आधार पर मुआवजा दिया जा रहा है। आर्थिक मामलों में, कानून निर्माता को एक व्यापक अक्षांश दिया जाता है और न्यायालय व्यावहारिक अनुभवों और कानून निर्माताओं द्वारा देखी गई अन्य समस्याओं के आधार पर ऐसे विधानों में प्रयोग करने की अनुमति देता है। इस तरह के कानून को चुनौती देते हुए, न्यायालय एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण नहीं अपनाता है। कुछ बलिदान हमेशा अधिक से अधिक भलाई के लिए किए जाने चाहिए, और जब तक कि इस तरह के बलिदान प्रथम दृष्टया स्पष्ट और स्पष्ट रूप से मनमाने के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कठोर और असमान नहीं होते हैं, तब तक अदालत द्वारा इनमें हस्तक्षेप किया जाएगा। [पैरा 17] [133-सी-जी]

1.12 अधिनियम, 2013 की धारा 327 की उप-धारा (7) में प्रावधान है कि अधिनियम, 2013 की धारा 326 और 327 को लागू नहीं किया जाएगा।

आई. बी. सी. के तहत परिसमापन की स्थिति में लागू, जो आई. बी. सी. के अधिनियम को देखते हुए आवश्यक हो गया है और यह आई. बी. सी. के तहत किसी कंपनी के परिसमापन के संबंध में लागू होता है, अधिनियम, 2013 की धारा 327 (7) को मनमाना और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है। आई. बी. सी. के तहत किसी कंपनी के परिसमापन के मामले में, आई. बी. सी. के तहत कंपनी के परिसमापन के मामले में, आई. बी. सी. की धारा 36 (4) के अधीन आई. बी. सी. की धारा 53 के अनुसार परिसंपत्तियों का वितरण करना होगा। [पैरा 18] [133-एच; 134-ए-बी]

मनीष कुमार बनाम। भारत संघ और एएनआर। (2021) 5 एस. सी. सी. 1; स्विस् रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और एन. आर. वी. भारत संघ और ओआरएस। (2019) 4 एससीसी 17: [2019] 3 एससीआर 535;

लघु औद्योगिक निर्माता संघ
(पंजीकृत) वी। भारत संघ और ओआरएस। (2021) 8 एससीसी [2023] 6 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्राइवेट लिमिटेड v. एडलवाइस परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (2021) 9 एस. सी. सी. 657; इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक और एन. आर. (2000) 4 एससीसी 406: [2000] 2 एस. सी. आर. 1102; आंध्र बैंक बनाम आधिकारिक परिसमापक और एएनआर। (2005) 5 एससीसी 75: [2005] 2 एस. सी. आर. 776; इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक और ए. एन. आर. (2018) 1 एस. सी. सी. 407 [2017] 8 एस. सी. आर. 33; आर्सेलरमिटल इंडिया प्राइवेट

सीमित वी। सतीश कुमार गुप्ता और अन्य। (2019) 2 एससीसी 1: [2018] 12 एस. सी. आर. 362; अरुण कुमार जगतारामका बनाम जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और एएनआर। (2021) 7 एससीसी

474 ; शेष नाथ सिंह और अन्न। वी. बैद्यवती

शेओराफुली सहकारी बैंक लिमिटेड और ए. एन. आर. (2021) 7 एससीसी 313; आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ और ओआरएस। (1981) 4 एस. सी. सी. 675 [1982] 1 एस. सी. आर. 947; रुस्तम कावासजी

कूपर वी। भारत संघ (1970) 1 एससीसी 248: [1970] 3 एस. सी. आर. 530; दिल्ली विज्ञान मंच और अन्य। वी. भारत संघ और एएनआर। (1996) 2 एससीसी 405: [1996] 2 एससीआर 767; बाल्को कर्मचारी संघ (विनियमित) v. भारत संघ और ओआरएस। (2002) 2 एससीसी 333: [2001] 5 पूरका एस. सी. आर. 511; कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त बनाम आधिकारिक

एस्के फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का परिसमापक (2011) 10 एस. सी. सी. 727: [2011] 15 एससीआर 336; भूपिंदर सिंह बनाम।

यूनिटेक लिमिटेड (2022) 8 एस. सी. सी. 749; स्विस् रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा। वी. भारत संघ और अन्य (2019) 4 एस. सी. सी. 17: [2019] 3 एससीआर 535-संदर्भित को।

मामला कानून संदर्भ

(2021) 5 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

3.15

[2019] 3 एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

3.15

(2021) 8 एस. सी. सी. 511

पैरा

3.15

[2019] 16 एससीआर 275

संदर्भित किया गया है

पैरा

3,17

(2021) 9 एस. सी. सी. 657

संदर्भित किया गया है

पैरा

संदर्भित किया गया है

3,18

[2000] 2 एससीआर 1102

पैरा

संदर्भित किया गया है

पैरा 3,19 मोसर बेयर करमचारी यूनियन टीएचआर। राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनाम। भारत का संघ

[2005] 2 एससीआर 776

संदर्भित किया गया है

पैरा

3.19

[2017] 8 एससीआर 33

संदर्भित किया गया है

पैरा

4.9

[2018] 12 एससीआर 362

संदर्भित किया गया है

पैरा

4.9

(2021) 7 एस. सी. सी. 474

संदर्भित किया गया है

पैरा

4.9

(2021) 7 एस. सी. सी. 313

पैरा

4.9

संदर्भित किया गया है

[1982] 1 एससीआर 947

संदर्भित किया गया है

पैरा

4.20

[1970] 3 एससीआर 530

संदर्भित किया गया है

4.21

पैरा

[1996] 2 एससीआर 767

4.21

पैरा

संदर्भित किया गया है

[2001] 5 पूरक। एससीआर 511

4.21

पैरा

संदर्भित किया गया है

[2019] 3 एससीआर 535

8

पैरा

संदर्भित किया गया है

[2011] 15 एससीआर 336

संदर्भित किया गया है

11

पैरा

(2022) 8 एस. सी. सी. 749

संदर्भित किया गया है

11

पैरा

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: लेखन याचिका (सी) संख्या 421

2019 से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

के साथ

लेखन

याचिका (सी) सं। 777 और 2020 का 712।

के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अरविंद राज, पी. वेंकटरमन,

अमर्त्य शरण, राहुल सांगवान, चाणक्य द्विवेदी, अधिवक्ता। (क्यूरी दोस्तों)

गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , उज्ज्वल बनर्जी, स्वप्निल गुप्ता,

दिनकर सिंह, गगन गर्ग, रोहित सिंह, सुश्री अदिति गुप्ता, दीपक गोयल, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

बलबीर सिंह, एएसजी, नमन टंडन, सुश्री सुरभी सिंह, समरवीर

सिंह, सुश्री सागरिका कौल, सुश्री मोनिका बेंजामिन, के. गुरुमूर्ति, सुश्री आकांक्षा कौल, नवनजय महापात्रा, कानू अग्रवाल, टी. एस. शबरीश, अरविंद कुमार शर्मा, संचार आनंद, अरविंद कुमार, प्रह्लाद नारायण सिंह, श्रीमती लारा सिद्दीकी, देवेन्द्र सिंह, अंकुर मित्तल, सुश्री मीरा मुरली, सुश्री ऐश्वर्या पांडे, सुश्री पल्लवी प्रताप, सुश्री प्राची प्रताप, प्रशांत प्रताप, सुश्री नीमा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

2019 की लिखित याचिका (सी) संख्या 421

1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस रिट याचिका के माध्यम से

यह भी प्रार्थना की जाती है कि मंडमस की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी किया जाए ताकि मंडमस के वैधानिक दावों को छोड़ दिया जा सके। " दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 53 के तहत झरने तंत्र के दायरे से बाहर श्रमिकों का बकाया (इसके बाद या तो "आईबीसी" या "कोड" के रूप में संदर्भित)।

आगे यह प्रार्थना की जाती है कि आई. बी. सी. की धारा 53 को एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या देकर मंडमस की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट जारी किया जाए और आवश्यक निर्देश पारित किए जाएं जो याचिकाकर्ताओं को बिना किसी और देरी के 24 महीने के अपने बकाया को जारी करने में सक्षम बनाएगा।

लेखन याचिका (सी) सं। 777 और 2020 का 712

1.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इन रिट याचिकाओं के माध्यम से, संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि आई. बी. सी. की धारा 255 के अनुसार आई. बी. सी. की ग्यारहवीं अनुसूची के खंड 19 (ए) को अनुचित घोषित किया जाए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया जाए क्योंकि आई. बी. सी. की ग्यारहवीं अनुसूची के खंड 19 (ए) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 327 में उप-धारा (7) शामिल की गई है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 और 327 के आवेदन पर वैधानिक रोक लगाती है। आई. बी. सी. के तहत परिसमापन कार्यवाही के लिए कंपनी अधिनियम, 2013।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 327 की उप-धारा (7) को अनुचित और अनुच्छेद का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाए।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016, 2016 का अधिनियम 31, के वैध बकाया के वितरण के लिए अनुचित वर्गीकरण बनाता है आई. बी. सी. के तहत कंपनी के परिसमापन और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत कंपनी के परिसमापन की स्थिति में कर्मचारी।

मोसर बेयर करमचारी यूनियन टीएचआर। राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनामा भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

यह भी प्रार्थना की जाती है कि आई. बी. सी. की धारा 53 (1) (बी) (आई) के तहत परिकल्पित श्रमिकों के बकाया के वितरण को अनुचित घोषित किया जाए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया जाए, क्योंकि आई. बी. सी. की धारा 53 (1) (बी) (आई) श्रमिकों को देय बकाया को केवल आदेश की तारीख से पहले चौबीस महीने तक सीमित करती है।

परिसमापन और फिर उक्त श्रमिकों के बकाया को सुरक्षित लेनदारों के साथ समान रूप से श्रेणीबद्ध करें यदि ऐसे सुरक्षित लेनदारों ने आई. बी. सी. की धारा 52 में निर्धारित तरीके से प्रतिभूति छोड़ दी है।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि आई. बी. सी. के तहत परिसमापन की स्थिति में भी कामगारों के बकाया का निपटान धारा 326 के तहत निर्धारित उचित सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए। 2. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन न्यायमित्र के रूप में उपस्थित हुए हैं। श्री गोपाल शंकरनारायणन, विद्वान वरिष्ठ

अधिवक्ता, याचिकाकर्ता (ओं) की ओर से पेश हुए हैं। श्री बलवीर सिंह, विद्वान ए. एस. जी. प्रतिवादी-भारत संघ की ओर से पेश हुए हैं।

3. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन ने सबसे पहले हमें कंपनी अधिनियम के विधायी इतिहास और

अधिमान्य भुगतान और दिवाला और दिवालियापन संहिता का निर्माण भी।

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956, जैसा कि कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1985 से पहले मौजूद था, किसी भी पक्ष को किसी भी "अधिमान्य भुगतान" का प्रावधान नहीं करता था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1985 में कंपनी (संशोधन) विधेयक, 1985 ने धारा 529 की उप-धारा (1), धारा 529 (3) को शामिल करके "श्रमिकों", "श्रमिकों के बकाया" और "श्रमिकों के हिस्से" की परिभाषा और धारा 529 ए के माध्यम से "अधिमानी अधिमान्य भुगतान" के लिए परंतुक पेश करने की मांग की थी।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए उद्देश्यों और कारणों का विवरण यह सुनिश्चित करने के लिए था कि कंपनी उन श्रमिकों को भी वितरित की जाती है जिनके श्रम और प्रयास

यह कंपनी की पूँजी का एक हिस्सा है। परिणामस्वरूप, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1985 के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 1956 में "श्रमिकों के हिस्से" और "अधिमान्य भुगतान" के विचार को पेश किया गया और स्पष्ट किया गया।

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 और धारा 529-ए का संचयी अध्ययन इंगित करता है कि सबसे पहले, प्रत्येक सुरक्षित लेनदार की प्रतिभूति को परि [2023] 6 एस. सी. आर. के अधीन माना जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी के पक्ष में पासू प्रभार-कर्मचारी, की सीमा तक

श्रमिकों का हिस्सा। दूसरा, जब प्रतिभूति प्राप्त लेनदार अपनी प्रतिभूति का एहसास करने का विकल्प चुनता है, तो ऐसे प्रतिभूति प्राप्त लेनदार के कारण होने वाले ऋण का इतना हिस्सा जिसे वह परंतुक या अपनी प्रतिभूति में श्रमिकों के हिस्से की राशि, जो भी कम हो, के आधार पर प्राप्त नहीं कर सकता है, उसे श्रमिकों के बकाया के बराबर माना जाएगा। तीसरा, धारा 529 (1) प्रावधान (सी) में वर्णित श्रमिकों के बकाया और सुरक्षित लेनदार के ऋण अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तरजीही भुगतान और श्रेणी समान रूप से उत्तीर्ण। ये ऋण पूर्ण रूप से देय होते हैं, जब तक कि संपत्ति उन्हें पूरा करने के लिए अपर्याप्त न हो, इस स्थिति में वे समान अनुपात में कम हो जाएंगे।

3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 530, जब यह प्रदान करती है -

" तरजीही भुगतान ", धारा 530 (1) (बी) की उप-धारा (2) में सीमा के अधीन, 12 महीने की अवधि तक सरकारी बकाया और एक कर्मचारी के वेतन या वेतन को प्रासंगिक तिथि से पहले 12 महीने के भीतर 4 महीने से अधिक की अवधि तक सीमित करता है।

3.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनी अधिनियम के अधिनियमन से पहले,

2013 , कंपनी अधिनियम, 1956 में सुधार के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इनमें से दो समितियाँ और उनके प्रस्ताव उन मुद्दों का संकेत हैं जिन्हें एक नए, नवीनीकृत कानून के माध्यम से संबोधित करने की मांग की गई थी। वर्ष 2000 में, दिवाला और कंपनियों के समापन से संबंधित कानून पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट थी -

न्यायमूर्ति वी. बालकृष्ण एराडी की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया

("एराडी समिति" के रूप में लोकप्रिय)। उसके द्वारा प्राप्त विभिन्न सुझावों पर विचार करने पर, इराडी समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की कि यह सुनिश्चित करने के लिए उचित विधायी कार्रवाई की जानी चाहिए कि सभी "कंपनी के कर्मचारियों" और उसके सुरक्षित लेनदारों के दावों को समान श्रेणी में रखा जाए। इसके बाद 2005 में डॉ. जमशेद जे. ईरानी की अध्यक्षता में कंपनी कानून, 2005 पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ईरानी समिति ने अपने समक्ष प्रस्तावों पर विचार करने पर सिफारिश की कि परिसमापन के प्रशासन की लागत और खर्चों से संबंधित दावों के भुगतान के बाद उनके दावों के संबंध में सुरक्षित लेनदारों की स्थिति "कर्मचारियों" के साथ समान होनी चाहिए।

3.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन दोनों समितियों का ध्यान "कंपनी के कर्मचारियों" के दावों को सुरक्षित लेनदारों के साथ लाने पर था, जब उस दिन के मौजूदा प्रावधान में केवल यह निर्दिष्ट किया गया था कि "श्रमिकों का बकाया" सुरक्षित लेनदारों के साथ समान होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन दोनों रिपोर्टों के बाद एम. ओ. एस. ई. आर. बी. ए. ई. आर. करामचारी यूनियन टी. एच. आर. का गठन किया गया।

राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनाम। भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

कंपनी अधिनियम, 1956 में अब धारा 326 (1) में एक प्रावधान और धारा 326 (2) में संशोधन शामिल होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों को 2 साल की अवधि के लिए देय मजदूरी/वेतन समाप्त होने की स्थिति में सुरक्षित है। इस विधायी परिवर्तन के लिए दिया गया तर्क समाप्त होने की स्थिति में श्रमिकों के हितों की रक्षा करना था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि परिणामस्वरूप, कंपनी अधिनियम, 2013, जैसा कि अधिनियमित किया गया था, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 और 529-ए की संरचना को ज्यादातर बनाए रखते हुए, धारा 326 (1) में परंतुक पेश किया और धारा 326 (2) को भी संशोधित किया।

3.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस परिवर्तन का परिणाम यह था कि धारा 325 (1) प्रावधान (सी) के अनुसार सुरक्षित लेनदारों के लिए श्रमिकों के बकाया और बकाया को समान माना जाता है, लेकिन परिसंपत्तियों की बिक्री के 30 दिनों की अवधि के भीतर समाप्त करने के आदेश से पहले 2 साल की अवधि के लिए श्रमिकों को देय मजदूरी और वेतन का भुगतान अन्य सभी ऋणों के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और यह सुरक्षित लेनदारों की प्रतिभूति पर ऐसे शुल्क के अधीन होगा जो निर्धारित किया जाए। महत्वपूर्ण रूप से, कर्मचारियों के स्वामित्व वाले सरकारी बकाया और मजदूरी या वेतन कंपनी अधिनियम, 1956 की तरह ही सीमित रहे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ध्यान देने योग्य एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि "श्रमिकों के बकाया" की परिभाषा

इसमें पेंशन निधि, उपदान निधि और भविष्य निधि राशि शामिल हैं और परिसमापन के मामले में उक्त राशि का कोई अपवर्जन नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, "ओवरराइडिंग" के संबंध में कानून की स्थिति कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अधिमान्य भुगतान और "अधिमान्य भुगतान" यह है कि श्रमिकों के हिस्से की सीमा तक प्रत्येक सुरक्षित लेनदार की प्रतिभूति की संपत्ति पर श्रमिकों का प्रभार होता है, श्रमिकों का बकाया सुरक्षित लेनदारों को देय ऋण और विशेष रूप से मजदूरी या वेतन [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समापन आदेश से पहले 2 साल की अवधि के लिए श्रमिकों को देय राशि का भुगतान अन्य सभी ऋणों की तुलना में प्राथमिकता से किया जाएगा।

3.9 कि उसके बाद श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ

अधिवक्ता और न्यायमित्र हमें आई. बी. सी. के निर्माण में ले गए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिवालियापन कानून सुधार समिति ने 04.11.2015 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट में दिवाला और दिवालियापन की कार्यवाही की मौजूदा व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तनों पर चर्चा की गई और अन्य कारणों के साथ-साथ यह भी बताया गया कि कानून की मौजूदा स्थिति में बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिवालियापन कानून सुधार समिति (बी. एल. आर. सी.) रिपोर्ट के महत्वपूर्ण हिस्सों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

आई.

समिति ने नोट किया कि परिचालन ऋणदाताओं में शामिल होंगे

कर्मचारी और कर्मचारी जिनका पिछला भुगतान देय है।

इसके अलावा, समिति ने नोट किया कि केंद्र और राज्य

ii.

सरकारी बकाया राशि को प्राथमिकता के आधार पर सभी प्रकार के ऋणों के अलावा असुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं के नीचे रखा जाएगा।

सुरक्षित लेनदार।

समिति यह भी स्पष्ट रूप से नोट करती है कि परिसमापन के तहत

iii.

[illegible]

iv.

इसके बाद समिति ने भारत में कानून लाने के लिए

वैश्विक प्रथा के अनुरूप, परिसमापन में भुगतान की प्राथमिकता स्थापित की गई और तदनुसार निर्देश तैयार किए गए

दिया गया। जैसा कि प्रस्तावित है, आई. आर. पी. और परिसमापन की लागत पहले स्थान पर होगी। उसके बाद, आई. आर. पी. की शुरुआत से 3 महीने तक के सुरक्षित लेनदारों और श्रमिकों के बकाया को समान प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद देय राशि का भुगतान करना था

कर्मचारियों की सीमा-3 महीने तक। अगले स्तर के रूप में, परिसमापन शुरू होने की तारीख से 12 महीने पहले शुरू होने वाली और परिसमापन शुरू होने की तारीख से 3 महीने पहले समाप्त होने वाली 9 महीने की अवधि के लिए श्रमिकों के बकाया को क्रमबद्ध किया जाना था।

असुरक्षित वित्तीय लेनदारों को देय राशि के साथ।

V. समिति ने यह भी नोट किया कि इस पर कुछ बहस हुई थी

क्या कंपनी अधिनियम, 2013 में श्रमिकों को प्राथमिकता दी गई है

इसे नए कोड में रखा जाना चाहिए।

मोसर बेयर कर्मचारी यूनियन टीएचआर। राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनामा भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

और कंपनी अधिनियम, 2013, कानून की स्थिति के उचित संज्ञान के साथ, जैसा कि तब मौजूद था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कानून की स्थिति की समीक्षा करने और आई. बी. सी. के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट ने सिफारिश की है कि श्रमिकों के बकाया को 3 महीने तक सीमित किया जाएगा और सुरक्षित लेनदारों के साथ समान प्राथमिकता होगी और उसके बाद, शेष बकाया असुरक्षित लेनदारों के साथ रैंक करेगा।

3.11 यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. को 2015 में एक विधेयक के रूप में पेश किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 36, जैसा कि विधेयक में पेश किया गया है, के लिए प्रावधान किया गया है

परिसमापन संपदा का गठन। विधेयक में धारा 36 (4) (ए) (iii) में कहा गया है कि कर्मचारी पेंशन के संबंध में योगदान

रिपोर्ट में विधेयक में निहित प्रावधानों के संबंध में दो महत्वपूर्ण सिफारिशों की गईं। सबसे पहले, श्रमिकों और कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर ध्यान देने के बाद, यह सिफारिश की गई थी कि भविष्य निधि, पेंशन कोष और ग्रेच्युटी कोष को धारा 36 के तहत परिसमापन संपत्ति से बाहर रखा जाए, क्योंकि वे श्रमिकों और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा, इस अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद कि कर्मचारियों के बकाया का भुगतान कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित योजना के अनुसार किया जाना है, संयुक्त समिति

सिफारिश की गई कि चूंकि सरकार को बकाया राशि का भुगतान परिसमापन शुरू होने की तारीख से दो साल पहले किया जा रहा है, इसलिए श्रमिकों के बकाया का भुगतान भी परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले 12 महीने की मौजूदा अवधि के बजाय दो साल की अवधि के लिए किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह ध्यान में रखते हुए इसकी सिफारिश की गई थी कि कर्मचारी "किसी भी कंपनी के प्रमुख केंद्र" हैं और उनके हित [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उनकी रक्षा की जानी चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संयुक्त को ध्यान में रखते हुए

प्रस्तुत किया कि आई. बी. सी. की धारा 36 (4) (ए) (iii) अब भविष्य निधि, पेंशन से किसी भी कर्मचारी या कर्मचारी को देय सभी राशियों को बाहर करती है। परिसमापन संपदा परिसंपत्तियों में शामिल किए जाने से निधि और उपदान निधि। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. की धारा 53 (1) (बी) (आई) और (2) अब श्रमिकों के बकाया को 2 साल की अवधि के लिए क्रमबद्ध करती है।

परिसमापन प्रारंभ होने की तिथि और सुरक्षित लेनदारों द्वारा अपनी प्रतिभूति समान अवधि छोड़ने की स्थिति में उन्हें देय ऋण। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कर्मचारियों का बकाया धारा 53 (1) (सी) में रखा गया है, जो 12 महीने की अवधि तक सीमित है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बकाया धारा 53 (1) (ई) (आई) में रखा गया है, जो 2 साल की अवधि तक सीमित है और असुरक्षित लेनदारों की अवधि से कम है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

इसलिए, परिणाम यह है कि कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रदान की गई स्थिति और झरना तंत्र को अब समझदारी से लागू करने के बाद बदल दिया गया है और परिणामस्वरूप, श्रमिकों के बकाया को परिसमापन से पहले 24 महीने तक सीमित कर दिया गया है।

प्रारंभ की तारीख। पूर्ववर्ती शासन से शुरू किए गए परिवर्तन कानून और परामर्श प्रक्रिया के जैविक विकास के आधार पर किए गए हैं, जो परिसमापन को नियंत्रित करने वाली एक नई संहिता की आवश्यकताओं पर उचित विचार करने के बाद किए गए हैं। 3.12 यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. की धारा 53 के स्पष्टीकरण (ii) में कहा गया है कि "श्रमिकों का बकाया" शब्द का वही अर्थ होगा जो निर्धारित किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 में। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद, आई. बी. सी. की ग्यारहवीं अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव है -

कंपनी अधिनियम, 2013 में बनाया जाए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि महत्वपूर्ण रूप से, अनुसूची के खंड 18 में कंपनी अधिनियम की पूर्ववर्ती धारा 325 को हटा दिया गया है।

2013. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुसूची का खंड 19 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 में संशोधन करता है। इसके बाद, अनुसूची का खंड 20 कंपनी अधिनियम, 2013 में धारा 327 (7) को सम्मिलित करता है जिसमें कहा गया है कि आई. बी. सी. के तहत परिसमापन की स्थिति में धारा 326 और धारा 327 लागू नहीं होगी। आई. बी. सी. की धारा 53 स्पष्टीकरण (ii) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 327 (7) के एक संयुक्त पठन से संकेत मिलता है कि आई. बी. सी. में संदर्भ द्वारा केवल "श्रमिकों के बकाया" का अर्थ शामिल किया गया है। हालाँकि, झरना तंत्र, जैसा कि आई. बी. सी. द्वारा पूरी तरह से बदल दिया गया है, इन "श्रमिकों के बकाया" पर लागू होगा न कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 में निहित झरना तंत्र पर। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 327 (7) को लागू करने का कारण केवल जलप्रपात तंत्र के अनुप्रयोग और मोसर बेयर करामचारी यूनियन टीएचआर के तौर-तरीकों को बाहर करना है।

राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनाम। भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित है जिसे अब आई. बी. सी. के माध्यम से बदल दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, यह तर्क कि कंपनी अधिनियम, 2013 से झरना तंत्र आई. बी. सी. के तहत भी लागू होना चाहिए, पूरी तरह से असमर्थनीय और अव्यवहारिक होगा।

3.13 यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाद में, दिवाला विधि समिति ने 2018 में श्री इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में संक्षिप्त प्रतिक्रियाएँ थीं -

आई. बी. सी. के संबंध में उठाई गई टिप्पणियों और मुद्दों की समिति। यह प्रस्तुत किया जाता है कि महत्वपूर्ण रूप से, श्रमिकों के बकाया के मुद्दे को उठाने वाले सभी प्रश्नों को या तो सुरक्षित लेनदारों के साथ अनुचित रूप से क्रमबद्ध किया गया था या श्रमिकों के बकाया को आई. बी. सी. के तहत संरक्षित नहीं किया गया था, समिति ने नोट किया कि श्रमिकों के हितों की रक्षा आई. बी. सी. द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के अनुरूप की गई थी।

3.14 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, विधायिका के माध्यम से

आई. बी. सी. ने कानून की मौजूदा प्रणाली को दुरुस्त करने का प्रयास किया है और एक अलग तरीका प्रदान किया है जिसके माध्यम से परिसमापन कार्य करेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, कंपनी को बंद करने की योजना को ध्यान में रखते हुए, जलप्रपात तंत्र और तरजीही भुगतान किए जा रहे थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि निश्चित रूप से, श्रमिकों के बकाया को एक परिभाषित प्रकार के सुरक्षित लेनदारों के साथ समान प्राथमिकता दी गई थी और समापन के आदेश से पहले दो वर्षों के लिए बकाया मजदूरी और वेतन को पूर्ण प्राथमिकता मिलनी थी। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इसके विपरीत, आई. बी. सी. की योजना कंपनी अधिनियम, 2013 से अलग है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. में ध्यान कंपनी को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है और यह केवल अंतिम उपाय के रूप में है कि परिसमापन की परिकल्पना की गई है। परिसमापन में, बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट के समय से, भुगतान प्राथमिकता को परिभाषित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और व्यवस्थित रूप से, श्रमिकों का बकाया 3 महीने से बढ़कर 12 महीने हो गया है और अब 24 महीने हो गया है ताकि वे अपनी प्रतिभूति छोड़ने वाले सुरक्षित लेनदारों के बराबर हो सकें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. का यह विकास एक परामर्श प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हुआ है, श्रमिकों के बकाया की स्थिति की कई मौकों पर समीक्षा की गई है और विधायिका ने अपने विवेक से इसे परिसमापन शुरू होने की तारीख से 24 महीने पहले की अवधि तक सीमित करने का विकल्प चुना है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा जाल की रक्षा के लिए पेंशन कोष, ग्रेच्युटी कोष और भविष्य निधि को परिसमापन संपत्ति से बाहर रखा गया है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत मौजूदा योजना में आई. बी. सी. के माध्यम से किए गए परिवर्तन असंवैधानिक नहीं होंगे।

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.15 श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और न्यायमित्र ने आगे प्रस्तुत किया है कि इस माननीय न्यायालय ने

जब आर्थिक विधानों की बात आती है तो निर्णयों में "न्यायिक हाथ बंद करने" के सिद्धांत पर विचार किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आर्थिक मामलों में, कानून निर्माता को एक व्यापक अक्षांश दिया जाता है और न्यायालय व्यावहारिक अनुभवों और कानून निर्माताओं द्वारा देखी गई अन्य समस्याओं के आधार पर ऐसे विधानों में प्रयोग करने की अनुमति देता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के कानून को चुनौती देने में, न्यायालय एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण नहीं अपनाता है। रिलायंस को मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसलों पर रखा गया है।

भारत और एन. आर. , (2021) 5 एस. सी. सी. 1 (पारस 169,249-251); स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम भारत संघ और अन्य। , (2019) 4

एस. सी. सी. 17 [(पैरा 17-24,25-28) [आई. बी. सी. की वस्तुओं के लिए] आर/डब्ल्यू पैरा 120]; लघु औद्योगिक निर्माता संघ (पंजीकृत)

बनाम भारत संघ और अन्य। , (2021) 8 एस. सी. सी. 511 (पारस 60-72)। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि निर्णयों के एक समूह में देखा गया है, सार्वजनिक हित को देखते हुए और इसे एक आर्थिक उपाय मानते हुए, एक कानून के तहत एक निहित अधिकार को किसी अन्य कानून द्वारा छीन लिया जा सकता है।

3.16 आई. बी. सी. और उचित वर्गीकरण पर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और न्यायमित्र श्री के. वी. विश्वनाथन ने कहा है कि

स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर का मामला। (ऊपर), यह न्यायालय आई. बी. सी. की धारा 53 के तहत झरना तंत्र सहित आई. बी. सी. के कई प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने से संबंधित था, भले ही यह परिचालन लेनदारों के कहने पर था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. के अधिनियमन के उद्देश्यों और कारणों को ध्यान में रखने के बाद, इस माननीय न्यायालय ने माना कि वित्तीय लेनदारों के वर्गीकरण के लिए एक बोधगम्य अंतर मौजूद है और आई. बी. सी. के तहत परिचालन लेनदार। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य पर निर्भरता रखते हुए आई. बी. सी. की धारा 53 को भी इस उचित वर्गीकरण के दृष्टिकोण से बरकरार रखा गया था।

3.17 आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति बनाम सतीश कुमार गुप्ता के मामले में।

और ओआरएस। , (2020) 8 एस. सी. सी. 531, यह न्यायालय इस बात से चिंतित था कि क्या एक समाधान योजना वित्तीय लेनदारों के बराबर परिचालन लेनदारों के साथ व्यवहार करना था और आगे आई. बी. सी. में किए गए संशोधनों के साथ जो सी. आई. आर. पी. प्रक्रिया के तहत परिचालन लेनदारों को न्यूनतम परिसमापन मूल्य प्रदान करता था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने उक्त निर्णय में कहा

कि "सभी के लिए समानता" के सिद्धांत को वित्तीय और मोसर बेयर कर्मचारी संघ के साथ व्यवहार करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है।

राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनाम। भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

परिचालन लेनदारों के बराबर यह आई. बी. सी. के पूरे उद्देश्य को विफल कर देगा। इस न्यायालय ने यह भी माना कि आई. बी. सी. में किए गए संशोधन जो परिचालन लेनदारों को न्यूनतम परिसमापन मूल्य की गारंटी देते हैं, अनुच्छेद 14 के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं हैं।

3.18 उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया है कि घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड बनाम एडलवाइस के मामले में

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, (2021) 9 एस. सी. सी. 657, यह न्यायालय इस बात से चिंतित था कि क्या अनुमोदित समाधान योजना सरकार के लिए बाध्यकारी थी, चाहे वह संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा आई. बी. सी. की धारा 31 में किए गए संशोधन से पहले हो या बाद में। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि संशोधन प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक था और अनुमोदित समाधान योजना सरकार के लिए बाध्यकारी होगी। ऐसा मानते हुए, इस न्यायालय ने योजना को सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी बनाने, एक साफ स्लेट बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाधान प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई आश्चर्यजनक दावा सामने न आए, विधायी इरादे पर ध्यान दिया।

3.19 कंपनी अधिनियम की धारा 529 और 529-ए के तहत "श्रमिकों के हिस्से" की व्याख्या पर, इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक और ए. एन. आर. के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जाता है।, (2000) 4 एस. सी. सी. 406 और आंध्र बैंक बनाम आधिकारिक परिसमापक और ए. एन. आर. , (2005) 5 एससीसी 75।

3.20 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाए और प्रार्थना के अनुसार राहत प्रदान की जाए।

4. हमने सुना है कि विद्वान ए. एस. जी. श्री बलबीर सिंह पेश हो रहे हैं।

प्रत्यर्थी की ओर से-भारत संघ। 4.1 श्री बलबीर सिंह, विद्वान एसजी ने हमें कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से, धारा 59 ए, 529 ए, 530 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों पर ले गए हैं।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि शुरू में दिवालिया कंपनियों को बंद करने के मामले में दिवालिया प्रक्रिया की धारा 325 के तहत व्यवस्था की गई थी।

अधिनियम, 2013। हालाँकि, आई. बी. सी. के आगमन पर अधिनियम, 2013 की धारा 325 को डब्ल्यू. ई. एफ. 15.11.2016 से हटा दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, आज तक, दिवालिया होने के मामले में समापन की कार्यवाही कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा नियंत्रित नहीं है और आई. बी. सी. के प्रावधान ही एकमात्र हैं।

ऐसी स्थिति से निपटने के लिए लागू कानून क्योंकि यह अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके अलावा, अधिनियम, 2013 की धारा 327 (7) के तहत डब्ल्यू. ई. एफ. 15.11.2016 में एक संशोधन लाया गया था जिसमें [2023] 6 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह स्पष्ट किया गया है कि आई. बी. सी. के तहत परिसमापन की स्थिति में अधिनियम, 2013 की धारा 326 और धारा 327 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल किसी भी समापन के मामले में

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 और 327 प्रासंगिक हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि धारा 326 और 327 के तहत कार्यवाही को समाप्त करने के मामले में निम्नलिखित प्रासंगिक विशेषताएं हैं। अधिनियम, 2013:

प्रतिभूति में श्रमिकों के हिस्से का भुगतान सभी को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।



अन्य ऋण;

हालांकि, 24 महीने की अवधि के लिए देय श्रमिकों के बकाया (ख) (i) और (ii) का भुगतान अन्य सभी को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

ऋण (सुरक्षित लेनदारों के कारण ऋण सहित)। इसका मतलब है कि 24 महीने की अवधि के लिए मजदूरी/वेतन हर अन्य दावे/ऋण (प्रतिभूति के कारण ऋण सहित) से अधिक है।

लेनदार)।

- श्रमिकों के बकाया में भविष्य निधि, पेंशन निधि और

कर्मचारियों के कल्याण के लिए उपदान निधि या कोई अन्य निधि

कम्पनी द्वारा अनुरक्षित।

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि झरना तंत्र धारा 327 में दिया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 530 के समान है। यह है।

प्रस्तुत किया कि इसके बाद वर्ष 2016 में आई. बी. सी. शुरू किया गया है जिसमें श्रमिकों के बकाया को विधिवत संरक्षित किया गया है और भविष्य निधि, ग्रेच्युटी फंड और पेंशन फंड को परिसमापन संपत्ति से बाहर रखा गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. की धारा 53 के अनुसार, झरने के तंत्र में श्रमिकों के बकाया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि परिसमापन प्रक्रिया आई. बी. सी. के अध्याय III के तहत आती है, जिसमें धारा 33 से लेकर 54 तक शामिल हैं। आई. बी. सी. की धारा 36 परिसमापन संपदा के लिए प्रावधान करती है और आई. बी. सी. की धारा 36 (4) कुछ भुगतानों को निर्दिष्ट करती है जिन्हें परिसमापन संपदा परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया जाना है। इसलिए, उक्त प्रावधान के अनुसार, इन सभी बकाया ऋणों को परिसमापन संपदा परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया जाना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रावधान के अनुसार, भविष्य

निधि, पेंशन निधि और उपदान निधि से किसी भी कर्मचारी या कर्मचारी को देय सभी भुगतान परिसमापन संपदा के तहत परिसंपत्तियों की सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे।

4.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. की धारा 53 के संबंध में परिसमापन परिसंपत्तियों की बिक्री को प्राथमिकता के निश्चित क्रम में वितरित किया जाएगा।

यह मोसर बेयर करमचारी यूनियन टीएचआर है। राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनाम। भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

प्रस्तुत किया कि धारा 53 के अनुसार, दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत और परिसमापन लागत का भुगतान सर्वोपरि है और इसका पूरा भुगतान किया जाएगा। परिसमापन लागत में परिसमापन प्रक्रिया की अवधि के दौरान कर्मचारियों को भुगतान किया गया वेतन और मजदूरी शामिल है ताकि कंपनी को चालू चिंता के रूप में बनाए रखा जा सके। इसके बाद, 24 महीने की अवधि के लिए श्रमिकों के बकाया का भुगतान प्रतिभूति छोड़ने की स्थिति में सुरक्षित लेनदारों के बकाया के साथ किया जाना है। श्रमिकों का बकाया और ऋण

कोई भी बकाया बकाया ऋण धारा 53 (1) (ई) (iii) की सीढ़ी से नीचे आता है। आई. बी. सी.

परिसंपत्तियों के पारदर्शी और न्यायसंगत परिसमापन के लिए विफलता। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. को दिवालिया होने के लिए एक जल-प्रवाह क्षण के रूप में पेश किया गया था। भारत में कानून जो कई अलग-अलग कानूनों जैसे अधिनियम, 2013, एस. आई. सी. ए., एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई., ऋण वसूली अधिनियम आदि के तहत समेकित प्रक्रिया को एक ही संहिता में परिवर्तित करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. का उद्देश्य व्यापक और समयबद्ध दिवालिया ढांचा पेश करना और सभी व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना था।

4.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि UNICITRAL विधायी गाइड पर

दिवाला कानून आई. बी. सी. का मसौदा तैयार करने के भारतीय अनुभव के लिए निर्देशात्मक था जो एक दिवाला कानून का प्रतिनिधित्व करने पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिवाला कानून और दिवालियापन कानून रिपोर्ट पर यू. एन. आई. सी. आई. टी. आर. ए. एल. विधायी गाइड को एक साथ पढ़ने से स्पष्ट होता है कि आई. बी. सी. के तहत दिवाला प्रक्रिया के लिए बनाई गई प्रक्रिया आर्थिक [2023] 6 एस. सी. आर. के आवंटन के लिए महत्वपूर्ण है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन पक्षों के बीच समन्वय जो प्रक्रिया में भाग लेते हैं या बाध्य होते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस माननीय न्यायालय ने आई. बी. सी. द्वारा प्राप्त व्यापक उद्देश्य और आर्थिक संतुलन को देखा है और इस प्रकार

इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक और ए. एन. आर. के मामले में वित्तीय संस्थानों सहित अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य को खोलने में आई. बी. सी. के काम करने और संचालन की सराहना की।, (2018) 1 एस. सी. सी. 407, आर्सेलरमिन्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य।, (2019) 2 एस. सी. सी. 1; अरुण कुमार जगतारामका बनाम जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और ए. एन. आर., (2021) 7 एस. सी. सी. 474 और शेष नाथ सिंह और अन्न। बनाम बैद्यवती शेओराफुली सहकारी

बैंक लिमिटेड और एन. आर., (2021) 7 एससीसी 313।

4.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. के उद्देश्यों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि एक कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट मृत्यु अपरिहार्य है। हालांकि, व्यापक सार्वजनिक हित में निगमित देनदार को पुनर्जीवित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, जिसमें न केवल निगम के कर्मचारी शामिल हैं। निगमित देनदार, बल्कि इसके लेनदार और देश की अर्थव्यवस्था के व्यापक हित में उत्पादित वस्तुएँ भी।

4.11 यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिवालियापन कानून सुधारों में

समिति (खंड 1) (नवंबर, 2015) में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि न्यास में इकाई द्वारा रखी गई परिसंपत्तियाँ (जैसे कर्मचारी पेंशन), कुछ वित्तीय बाजार संस्थानों के लिए संपात्तिक के रूप में रखी गई परिसंपत्तियाँ और परिचालन लेनदेन के हिस्से के रूप में रखी गई परिसंपत्तियाँ जहाँ इकाई का परिसंपत्ति पर अधिकार है, लेकिन उसका मालिक नहीं है, उन्हें परिसमापन संपत्ति से बाहर रखा जाएगा। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. के तहत झरना तंत्र के संबंध में भी बहस की गई और इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि कॉर्पोरेट दिवालियापन और समाधान प्रक्रिया और परिसमापन की लागत के बाद 3 महीने तक के श्रमिकों के बकाया को सुरक्षित लेनदार के साथ दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी।

4.12 यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाद में, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2015 पर संयुक्त समिति की एक रिपोर्ट तैयार की गई थी

और लोकसभा में 28.04.2016 पर प्रस्तुत किया गया जिसमें भविष्य निधि, पेंशन निधि और ग्रेच्युटी निधि को दिवालिया की परिसंपत्तियों और परिसंपत्तियों के परिसमापन से बाहर रखने के मुद्दे पर बहस की गई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक गहन जांच के बाद समिति का विचार था कि भविष्य निधि, पेंशन निधि और ग्रेच्युटी निधि श्रमिकों और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं और इसलिए, किसी कंपनी के परिसमापन या साझेदारी फर्म के दिवालिया होने की स्थिति में इसे सुरक्षित करने की आवश्यकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि समिति ने आगे कहा कि श्रमिक मोसर बेयर करामचारी यूनियन टीएचआर हैं।

राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनाम। भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

किसी भी कंपनी का प्रमुख केंद्र और किसी भी कंपनी के दिवालिया या दिवालिया होने की स्थिति में, कर्मचारी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं और इसलिए, उनके बकाया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए, भविष्य निधि, उपदान निधि या पेंशन निधि से किसी भी कर्मचारी या कर्मचारी को देय सभी राशियों को परिसमापन संपदा परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए, समिति ने निर्णय लिया कि आई. बी. सी. की धारा 53 के तहत प्रदान की गई 12 महीने की अवधि के लिए श्रमिकों के बकाया को परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले 24 महीने तक बढ़ाया जाए।

भविष्य निधि, पेंशन निधि और ग्रेच्युटी निधि, जिन्हें परिसमापन परिसंपत्तियों और परिसमापक के रूप में नहीं माना जाता है, का ऐसी निधियों पर कोई दावा नहीं है। कि इसलिए, श्रमिकों के बकाया का यह हिस्सा जानबूझकर परिसमापन प्रक्रिया से बाहर ले लिया गया है।

4.14 यह प्रस्तुत किया जाता है कि परिसमापन लागत मजदूरी को शामिल करती है और

परिसमापन प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों का वेतन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि परिसमापन लागत आई. बी. सी. की धारा 5 (16) में परिभाषित की गई है जिसमें परिसमापन की अवधि के दौरान परिसमापक द्वारा की गई लागत शामिल है, जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अधीन है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि परिसमापन प्रक्रिया के संबंध में, बोर्ड ने दिवाला को अधिसूचित किया है

दिया गया। **4.15** यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. की धारा 53 के तहत श्रमिकों और सुरक्षित लेनदार के संबंध में समान आधार पर रखा जाने वाला मुद्दा केवल उस मामले में है जिसमें सुरक्षित लेनदार ने अपनी प्रतिभूति छोड़ दी है और यह परिसमापन पूल का हिस्सा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. की धारा 52 विशेष रूप से परिसमापन कार्यवाही में सुरक्षित लेनदार के बारे में बताती है और विनियमन 21 ए [2023] 6 एस. सी. आर. के बारे में बात करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुरक्षित लेनदारों के मामले में प्रतिभूति ब्याज का अनुमान। यह है।

प्रस्तुत किया कि उक्त स्थिति पर प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट (मार्च, 2018) के साथ-साथ दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट (फरवरी, 2020) में विधिवत विचार किया गया है।

4.16 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि समिति ने फरवरी, 2020 की रिपोर्ट में विधिवत सहमति व्यक्त की कि वसूली के लिए प्राथमिकता सुरक्षित है। धारा 53 (1) (बी) (ii) के तहत लेनदारों को केवल प्रतिभूति ब्याज के मूल्य की सीमा तक लागू होना चाहिए जो प्रतिभूतिधारक द्वारा छोड़ दिया जाता है।

लेनदार। यह प्रस्तुत किया जाता है कि समिति ने नोट किया कि संहिता का उद्देश्य एक सामूहिक परिसमापन प्रक्रिया को बढ़ावा देना है और इस दिशा में, यह सुरक्षित लेनदारों को आई. बी. सी. की धारा 53 (1) (बी) के तहत अपने बकाया की वसूली में दूसरी सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करके अपने सुरक्षा हित को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है और उन्हें आई. बी. सी. के तहत सामान्य असुरक्षित लेनदारों के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि वे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत होते। कि उक्त प्रावधान का उद्देश्य समग्र मूल्य अधिकतमकरण को बढ़ावा देना है।

4.17 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके अलावा, समिति ने अपनी रिपोर्ट में

फरवरी, 2020 ने यह भी तय किया कि क्या सुरक्षित लेनदार कौन हैं एहसास हुआ कि उनके प्रतिभूति हित को भुगतान में योगदान देना चाहिए

कामगारों का बकाया। परिसमापन प्रक्रिया के विनियम 21 (ए) के लिए आवश्यक है कि जो सुरक्षित लेनदार अपने प्रतिभूति ब्याज का एहसास करते हैं, वे श्रमिकों के बकाया के भुगतान में योगदान करते हैं जैसा कि उनके पास होता यदि वे परिसमापन संपत्ति के लिए अपने प्रतिभूति हित को छोड़ देते। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार, विनियमन 21 ए के तहत प्रदान किए गए श्रमिकों के बकाया में योगदान करने की आवश्यकता, यह स्वीकार करती है कि श्रमिक प्रमुख हितधारक हैं और श्रमिकों को संरक्षित करने के प्रयासों की रीढ़ हैं। निगमित देनदार का व्यवसाय न केवल दिवालियापन शुरू होने से पहले बल्कि दिवालियापन कार्यवाही के दौरान भी।

4.18 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार, वस्तुओं की कल्पना करना और काम करना

आई. बी. सी. के अनुसार, यह स्पष्ट है कि आई. बी. सी. के अधिनियमन की तारीख से श्रमिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में जो सुरक्षित लेनदार द्वारा प्रतिभूति का त्याग या गैर-त्याग है, श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में, सुरक्षित लेनदार महत्वपूर्ण बाल कटवा रहे हैं और श्रमिकों को आई. बी. सी. की धारा 53 के अनुसार न्यायसंगत और उचित तरीके से न्यायसंगत आधार पर मुआवजा दिया जा रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

इसलिए, यह कहना अनुचित है कि उन्हें श्रमिकों के साथ श्रेणीबद्ध करना मनमाना है, ऐसा न हो कि धारा 53 को असंवैधानिक घोषित करना स्पष्ट रूप से मनमाना हो।

मोसर बेयर करमचारी यूनियन टीएचआर। राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनाम। भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

4.19 यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. की धारा 53 के तहत प्रदान किए गए झरने तंत्र की जांच से, यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार सहित अन्य हितधारकों ने उनके साथ गंभीर समझौता किया है।

वैधानिक बकाया की वसूली के संबंध में स्थिति ताकि मूल्य अधिकतमकरण को सक्षम किया जा सके और अस्वस्थ कंपनियों को चालू चिंता पर पुनर्जीवित किया जा सके आधार। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, यह कहने के लिए कि श्रमिक किसी भी तरह से हैं

अनुच्छेद 14 के तहत मनमानेपन या असमानता की धुन पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना गलत है। 4.20 यह आगे प्रत्यर्थी-भारत संघ की ओर से पेश हुए विद्वान ए. एस. जी. श्री बलबीर सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि आई. बी. सी.

आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखे गए और अभिनिर्धारित आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कानून होने के नाते, (1981) 4 एस. सी. सी. 675, अर्थव्यवस्था से संबंधित कानूनों को नागरिक अधिकारों को छूने वाले कानूनों की तुलना में अधिक अक्षांश के साथ देखा जाना चाहिए।

4.21 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और आर. के. गर्ग (उपरोक्त) (पैरा 8 और 16) के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करना; रुस्तम कावासजी कूपर बनाम भारत संघ, (1970) 1 एस. सी. सी. 248 (पैरा 63 और 17); दिल्ली विज्ञान मंच और अन्य। बनाम भारत संघ और अत्रा, (1996) 2 एस. सी. सी. 405 (पैरा 7); बाल्को कर्मचारी संघ (विनियमित) बनाम भारत संघ और अन्य, (2002) 2 एस. सी. सी. 333 (पैरा 46,47,92,93,94 और 98) में यह अभिनिर्धारित करने की प्रार्थना की गई है कि आई. बी. सी., 2016 की धारा 53 न तो मनमाना है और न ही आई. बी. सी. के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है।

भारत का संविधान।

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान वकील को विस्तार से उपस्थित होते हुए सुना है।

6. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस रिट याचिका के माध्यम से

2016. धारा 327 (7) के अनुसार, आई. बी. सी. के तहत परिसमापन की स्थिति में अधिनियम, 2013 की धारा 326 और 327 लागू नहीं होगी। अधिनियम, 2013 की धारा 326 और 327 एक समापन में तरजीही भुगतान का प्रावधान करती है। अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत। हालांकि, आई. बी. सी. के तहत नई व्यवस्था की शुरुआत को देखते हुए, आई. बी. सी. के तहत परिसमापन के मामले में, आई. बी. सी. की धारा 53 के अनुसार वितरण किया जाना है। इस स्तर पर, यह [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह ध्यान देने योग्य है कि आई. बी. सी. को डब्ल्यू. ई. एफ. 28.05.2016 और-आई. बी. सी. की धारा 53, परिसमापन के मामले में परिसंपत्तियों का वितरण अधिनियमित किया गया है।

आई. बी. सी. बनाना आवश्यक है। आई. बी. सी. की धारा 53 इस प्रकार है

((ii) यदि ऐसे प्रतिभूत लेनदार ने धारा 52 में निर्धारित तरीके से प्रतिभूति छोड़ दी है, तो किसी प्रतिभूत लेनदार को देय ऋण; (ग) मजदूरी और इसके अलावा अन्य कर्मचारियों का कोई भी बकाया भुगतान

(घ) असुरक्षित लेनदारों को देय वित्तीय ऋण; (ङ) निम्नलिखित देय राशि निम्नलिखित के बीच और उनके बीच समान रूप से क्रमबद्ध होगी:

((i) केंद्र सरकार और राज्य को देय कोई भी राशि।

परिसमापन प्रारंभ होने की तारीख से पहले की दो वर्ष की अवधि के पूरे या किसी भाग के संबंध में भारत की संचित निधि और किसी राज्य की संचित निधि, यदि कोई हो, के लिए प्राप्त होने वाली राशि सहित सरकार;

((ii) प्रतिभूति ब्याज लागू होने के बाद किसी भी राशि के भुगतान के लिए एक सुरक्षित लेनदार को देय ऋण; (च) कोई शेष ऋण और देय राशि;

(छ) तरजीही शेयरधारक, यदि कोई हो; और मोसर बेयर करामचारी यूनियन टीएचआर।

राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनाम। भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

(ज) इक्विटी शेयरधारक या भागीदार, जैसा भी मामला हो।

प्रत्येक वर्ग को देय आय से आनुपातिक रूप से उप-धारा (1) के तहत प्राप्तकर्ता, और संबंधित को आय

इस तरह की कटौती के बाद प्राप्तकर्ता को वितरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजन के लिए

(i) एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राप्तकर्ताओं के एक वर्ग के संबंध में आय के वितरण के प्रत्येक चरण में प्रत्येक ऋण का या तो पूरा भुगतान किया जाएगा या समान रूप से भुगतान किया जाएगा। प्राप्तकर्ताओं के समान वर्ग के भीतर अनुपात, यदि आय है

ऋणों को पूरी तरह से पूरा करने के लिए अपर्याप्त; और
(ii) "श्रमिकों का बकाया" शब्द का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 326 में दिया गया है।

आई. बी. सी. और आई. बी. सी. की धारा 53 के अधिनियमन को देखते हुए, अधिनियम, 2013 में संशोधन करना आवश्यक हो गया। धारा 327 की उप-धारा (7) के अनुसार, आई. बी. सी. के तहत परिसमापन की स्थिति में धारा 326 और 327 लागू नहीं होंगी। अधिनियम, 2013 में संशोधन करने और आई. बी. सी. के तहत परिसमापन की स्थिति में धारा 326 और 327 को बाहर करने का उद्देश्य और उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि किसी कंपनी के परिसमापन के संबंध में दो अलग-अलग प्रावधान नहीं हो सकते हैं। इसलिए, आई. बी. सी. के अधिनियमन को देखते हुए, अधिनियम, 2013 की धारा 326 और 327 की प्रयोज्यता को बाहर करना आवश्यक हो गया, जिसे याचिकाकर्ता की ओर से मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

6.1 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि धारा 327 की उप-धारा (7), जिसके अधिकार चुनौती के अधीन हैं, निम्नलिखित में लागू होगी -

आई. बी. सी. के तहत किसी कंपनी के परिसमापन का मामला। अर्थात्, आई. बी. सी. के अधीन किसी कंपनी के परिसमापन के मामले में, आई. बी. सी. की धारा 53 के प्रावधान और आई. बी. सी. के अन्य प्रावधान लागू होंगे क्योंकि आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत कंपनी को परिसमापन या समाप्त करने का आदेश दिया जाता है। इसलिए, केवल इसलिए कि पहले की व्यवस्था के तहत और अधिनियम, 1956/2013 के तहत किसी कंपनी को बंद करने के मामले में, श्रमिकों का बकाया सुरक्षित लेनदार, [2023] 6 एस. सी. आर. के बराबर हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ता आई. बी. सी. के तहत कंपनी के समापन/परिसमापन के मामले में समान लाभ का दावा नहीं कर सकता है। दलों द्वारा शासित किया जाएगा

आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत किसी कंपनी के परिसमापन के मामले में आई. बी. सी. के प्रावधान।

6.2 अब जहां तक आई. बी. सी. की धारा 53 का संबंध है, यह किसी कंपनी के परिसमापन के मामले में परिसंपत्तियों के वितरण का प्रावधान करता है।

आईबीसी। धारा 53 (1) (बी) के अनुसार परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले चौबीस महीने की अवधि के लिए श्रमिकों का बकाया श्रमिकों और सुरक्षित लेनदार के बीच समान रूप से होगा, यदि ऐसे सुरक्षित लेनदार ने निर्धारित तरीके से प्रतिभूति छोड़ दी है।

धारा 52। इसलिए, परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले चौबीस महीने की अवधि के लिए श्रमिकों का बकाया सुरक्षित लेनदार के बकाया के बराबर होगा। इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आई. बी. सी. की धारा 36 (4) के अनुसार, भविष्य निधि, पेंशन निधि और उपदान से किसी भी कर्मचारी या कर्मचारी को देय सभी राशि।

निधि परिसमापन संपदा परिसंपत्तियों में शामिल नहीं की जाएगी और परिसमापन में वसूली के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए, संसद/विधानमंडल द्वारा अपने विवेक से एक सचेत निर्णय लिया गया है कि किसी भी कर्मचारी/कर्मचारी को भविष्य निधि, पेंशन निधि और परिसमापन संपदा परिसंपत्तियों से उपदान निधि (धारा 36 (4) के अनुसार) से सभी देय राशियों को बाहर रखा जाए और परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले चौबीस महीने की अवधि के लिए श्रमिकों के बकाया को क्रमबद्ध किया जाए।

उक्त सीमा तक श्रमिकों के बकाया और सुरक्षित लेनदार के बकाया के बीच समान रूप से। इसलिए, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का मनमाना और उल्लंघनकारी नहीं कहा जा सकता है।

याचिकाकर्ता की ओर से। कानून की तय स्थिति के अनुसार, आई. बी. सी. एक पूर्ण संहिता है और आई. बी. सी. का उद्देश्य और उद्देश्य अधिनियम, 1956/2013 से पूरी तरह से अलग है। आई. बी. सी. एक नया दिवाला तंत्र है, इसलिए आई. बी. सी. के तहत प्रावधानों की तुलना पिछली व्यवस्था, अर्थात् कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के साथ नहीं की जा सकती है।

6.3 इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि श्रमिक और सुरक्षित लेनदार के संबंध में मुद्दे को समान रखा जा रहा है।

आई. बी. सी. की धारा 53 के तहत आधार केवल उस मामले में है जिसमें प्रतिभूति लेनदार ने अपनी प्रतिभूति छोड़ दी है और यह परिसमापन पूल के चरण का हिस्सा है।

मोसर बेयर करमचारी यूनियन टीएचआर। राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनामा भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

7. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 1, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था,

सरकार की अधिसूचना द्वारा, न्यायाधिकरण की राय है कि कंपनी के कार्य धोखाधड़ी के तरीके से किए गए हैं या कंपनी का गठन धोखाधड़ी और गैरकानूनी उद्देश्य के लिए किया गया है, या इसके मामलों के गठन या प्रबंधन में संबंधित व्यक्ति धोखाधड़ी, कदाचार, कदाचार के दोषी हैं, जिससे यह उचित हो जाता है कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाए; या यदि कंपनी ने लगातार पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए पंजीयक के साथ अपने वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरणी दाखिल करने में चूक की है; अंत में, यदि न्यायाधिकरण की राय है कि कंपनी को बंद करना उचित और न्यायसंगत है। 1 1 271. ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें कंपनी को न्यायाधिकरण द्वारा समाप्त किया जा सकता है। - (1) एक कंपनी, धारा 272 के तहत एक याचिका पर, न्यायाधिकरण द्वारा समाप्त की जा सकती है-(ए) यदि कंपनी ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है;

(ख) यदि कंपनी ने विशेष संकल्प द्वारा यह संकल्प लिया है कि कंपनी को न्यायाधिकरण द्वारा समाप्त कर दिया जाए;

(ग) यदि कंपनी ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हितों के खिलाफ काम किया है; (घ) यदि न्यायाधिकरण ने अध्याय XIX के तहत कंपनी को समाप्त करने का आदेश दिया है; (ङ) यदि इस अधिनियम के तहत अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, न्यायाधिकरण की राय है कि कंपनी के कार्य धोखाधड़ी के तरीके से किए गए हैं या कंपनी का गठन धोखाधड़ी और गैरकानूनी उद्देश्य से किया गया था या इसके मामलों के गठन या प्रबंधन में संबंधित व्यक्ति धोखाधड़ी, कदाचार या कदाचार के दोषी रहे हैं और यह उचित है कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाए; (च) यदि कंपनी ने लगातार पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए अपने वित्तीय विवरण या वार्षिक रिटर्न को पंजीयक के पास दाखिल करने में चूक की है; या

(छ) यदि न्यायाधिकरण की राय है कि यह न्यायसंगत और न्यायसंगत है कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

[2023] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7.1 अधिनियमित प्रावधान को तब तक लागू नहीं किया गया था जब तक कि इसे 15 नवंबर 2016 से 2016 के अधिनियम संख्या 31 और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के पैराग्राफ 10 में ग्यारहवीं अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया था। यह संहिता के अधिनियमन और प्रवर्तन के साथ हुआ, जो 15 नवंबर 2016 से भी लागू है। प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 3 में अब कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी को बंद करने के लिए केवल पांच आधारों की परिकल्पना की गई है। पहला आधार यह है कि कंपनी द्वारा

सरकार एक अधिसूचना द्वारा संतुष्ट है कि कंपनी के कार्य धोखाधड़ी से किए गए हैं, या कंपनी का गठन किया गया था धोखाधड़ी या गैरकानूनी उद्देश्य के लिए, या इसके मामलों के गठन या प्रबंधन में संबंधित व्यक्तियों को इसके संबंध में धोखाधड़ी, कदाचार या कदाचार का दोषी पाया गया है, जो कंपनी को समाप्त करना उचित बनाता है; यदि कंपनी ने चूक की है

लगातार पाँच वर्षों से तुरंत पहले के लिए पंजीयक के साथ वित्तीय विवरण और वार्षिक विवरणी दाखिल करने में; और अंत में यदि न्यायाधिकरण की राय है कि यह न्यायसंगत और न्यायसंगत है कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

2 संक्षेप में, "कोड"। 3 271. ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें कंपनी को न्यायाधिकरण द्वारा समाप्त किया जा सकता है। - धारा 272 के तहत एक याचिका पर एक कंपनी को न्यायाधिकरण द्वारा समाप्त किया जा सकता है-(ए) यदि कंपनी ने विशेष प्रस्ताव द्वारा निर्णय लिया है कि कंपनी को न्यायाधिकरण द्वारा समाप्त किया जाए;

(ख) यदि कंपनी ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हितों के खिलाफ काम किया है;

(ग) यदि पंजीयक या इस अधिनियम के तहत अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, न्यायाधिकरण की राय है कि कंपनी के कार्य धोखाधड़ी के तरीके से किए गए हैं या कंपनी का गठन धोखाधड़ी और गैरकानूनी उद्देश्य से किया गया था या इसके मामलों के गठन या प्रबंधन में संबंधित व्यक्ति इसके संबंध में धोखाधड़ी, कदाचार या कदाचार के दोषी हैं और यह उचित है कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाए; (घ) यदि कंपनी ने पंजीयक के पास अपने वित्तीय विवरण या लगातार पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने में चूक की है; या

(ङ) यदि न्यायाधिकरण की राय है कि यह न्यायसंगत और न्यायसंगत है कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

मोसर बेयर करमचारी यूनियन टीएचआर। राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनाम। भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

7.2 स्पष्ट रूप से, विधायिका ने अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 271 के खंड (ए) को हटा दिया है, जब कोई कंपनी भुगतान करने में असमर्थ है

ऋण, और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 271 का खंड (डी), जब किसी कंपनी को कंपनी अधिनियम के अध्याय XIX के तहत बंद करने का निर्देश दिया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013। वास्तव में, कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XIX को 2016 के अधिनियम संख्या 31 और संहिता के पैराग्राफ 8 में ग्यारहवीं अनुसूची के संदर्भ में 15 नवंबर 2016 से हटा दिया गया था। संहिता, जैसा कि अधिनियमित किया गया है, एक अलग और समेकित अधिनियम है जो विशेष रूप से दिवालिया कंपनियों से संबंधित है और उनसे संबंधित है।

और बकाया का भुगतान करने में असमर्थ है, और पहले कंपनी के पुनर्वास और पुनरुद्धार की संभावना का पता लगाने के लिए एक अधिदेश के साथ एक प्रक्रिया की परिकल्पना करता है, और अंतिम कॉल के रूप में विघटन/समापन।

7.3 यह महत्वपूर्ण है और जब हम याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई संवैधानिक चुनौती के प्रश्न की जांच करते हैं तो इसे उजागर किया जाना चाहिए, ताकि संहिता के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल न किया जा सके, जो दिवालिया और दिवालियापन के लिए तत्कालीन मौजूदा ढांचे को पूरी तरह से बदल देता है। ऐसा संकल्प जो अपर्याप्त, अप्रभावी और अनुचित देरी करने का दोषी हो। संहिता का अधिनियमन और उसके बाद किए गए संशोधन कई लोगों द्वारा विस्तृत परामर्श और विचार-विमर्श का परिणाम हैं।

समितियाँ, आयोग और विशेषज्ञ 4, एक ऐसे मामले में जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। पहले की स्थिति बहुत दूर थी

बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 और प्रतिभूतिकरण के बावजूद संतोषजनक और

वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002। इस संहिता को परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने, ऋण की उपलब्धता बढ़ाने और परिसंपत्तियों को संतुलित करने के लिए समयबद्ध तरीके से निगमित व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवालिया समाधान के उद्देश्य से लागू किया गया है।

दिवाला और दिवालियापन कोष की स्थापना के लिए सरकारी बकाया के भुगतान की प्राथमिकता में परिवर्तन और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों सहित सभी हितधारकों के हित। द.

4 देखें-दिवाला और कंपनियों के समापन से संबंधित कानून पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट, 2000, कंपनी कानून पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट दिनांक आई. डी. 1, कंपनी विधेयक, 2011 पर वित्त पर 15 वीं लोकसभा की स्थायी समिति की 57 वीं रिपोर्ट, दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट दिनांक आई. डी. 3, दिवाला और दिवालियापन संहिता पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट, 16 वीं लोकसभा की रिपोर्ट और दिवाला कानून समिति की रिपोर्ट दिनांक आई. डी. 2।

[2023] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी में सुधार करना और अधिक निवेश की सुविधा प्रदान करना है, जिससे उच्च आर्थिक विकास और विकास हो सके।

8. हम पहले श्रमिकों के बकाया की स्थिति पर संहिता को लागू करते समय व्यक्त की गई अलग-अलग राय का विस्तार से उल्लेख कर चुके हैं।

और वह पदानुक्रम जिसमें उन्हें रखा जाना चाहिए। झरना।

श्रमिकों के बकाया के संदर्भ में संहिता में अब निर्धारित तंत्र एक सुविचारित और विचारशील निर्णय है। जल प्रपात तंत्र और श्रमिकों के बकाया के लिए निर्धारित पदानुक्रम को संहिता के समग्र उद्देश्य में देखा जाना चाहिए, जो यह पता लगाने के लिए है कि क्या कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित किया जा सकता है ताकि नौकरियां न जाएँ, आर्थिक संपत्तियों का उपयोग अधिकतम हो, और एक प्रभावी कानूनी ढांचा हो जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों के हाथों में ऋण की व्यवहार्यता को बढ़ाता है। संहिता सुरक्षित पर वित्तीय प्रभाव को मान्यता देती है।

सार्वजनिक धन से निपटने वाले लेनदार या वित्तीय संस्थान, उनके रूप में

आर्थिक स्वास्थ्य आम जनता के साथ-साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तक उद्योग में आर्थिक विकास और नए निवेश नहीं होंगे, तब तक रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे, जो बदले में आर्थिक संकट, दिवालिया होने और दिवालिया होने का कारण बनेंगे। ये सभी जटिल आर्थिक मामले हैं जिनमें विभिन्न परस्पर विरोधी मामले हैं। हितों को संतुलित होना चाहिए और एकतरफा दृष्टिकोण के बजाय समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। प्रत्येक राय में योग्यता हो सकती है, लेकिन अदालत शायद ही विधायिका के लिए अपने स्वयं के ज्ञान या दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित कर सकती है, विशेष रूप से जब अधिनियम अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली जटिल वित्तीय और वाणिज्यिक चुनौतियों पर एक विचारशील और विवादास्पद समीक्षा का परिणाम है। इस संदर्भ में, यह न्यायालय, स्विस् रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य में परिचालन लेनदारों द्वारा किए गए भेदभाव की चुनौती पर संहिता की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए है। वी. भारत संघ और अन्य। 5 निम्नलिखित रूप में देखा गया था:

" न्यायिक हाथों में है आर्थिक कानून

21. इस देश में, यह न्यायालय आर. के. गर्ग बनाम. भारत संघ, (1981) 4 एस. सी. सी. 675 ने कहा है:

" 8. समान महत्व का एक अन्य नियम यह है कि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कानूनों को उससे अधिक अक्षांश के साथ देखा जाना चाहिए।

भाषण, धर्म आदि की स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकारों को छूने वाले कानून। होम्स, जे. से कम किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा है कि

5 (2019) 4 एससीसी 17.

आई. ओ. एस. ई. आर. बेयर करमचारी यूनियन टी. एच. आर. राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनाम। भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

विधायिका को जोड़ों में कुछ खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि इसे जटिल समस्याओं से निपटना पड़ता है जो किसी भी सिद्धांत या स्ट्रेटजैकेट सूत्र के माध्यम से समाधान को स्वीकार नहीं करते हैं और यह है

विशेष रूप से आर्थिक मामलों से संबंधित कानून के मामले में यह सच है।

जिन मामलों से निपटने के लिए आवश्यक समस्याओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जोड़ों में अधिक खेल को विधायिका को अनुमति दी जानी चाहिए। अदालत को अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक विनियमन के क्षेत्र में विधायी निर्णय को न्यायिक सम्मान देने के लिए अधिक झुकाव महसूस करना चाहिए जहां मौलिक मानवाधिकार शामिल हैं। यह चेतावनी इससे अधिक सम्मानपूर्वक कहीं भी व्यक्त नहीं की गई है।

मोरे वी की तुलना में डाउड जहाँ फ्रैंकफर्ट, जे. ने अपनी अनूठी शैली में कहा:

' उपयोगिताओं, कर और आर्थिक विनियमन मामलों में, विधायी निर्णय के प्रति न्यायिक सम्मान नहीं तो न्यायिक आत्म-संयम के अच्छे कारण हैं। आखिरकार विधायिका की सकारात्मक जिम्मेदारी है। अदालतों के पास केवल नष्ट करने की शक्ति है, पुनर्निर्माण की नहीं। जब इन्हें जोड़ा जाता है

आर्थिक विनियमन की जटिलता, अनिश्चितता, त्रुटि के लिए दायित्व, विशेषज्ञों के विस्मयकारी संघर्ष और घटनाओं द्वारा न्यायाधीशों को कितनी बार खारिज किया गया है, आत्म-सीमा को न्यायिक ज्ञान और संस्थागत प्रतिष्ठा और स्थिरता का मार्ग माना जा सकता है।

न्यायालय को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि "कानून व्यावहारिक समस्याओं के लिए निर्देशित है, कि आर्थिक तंत्र अत्यधिक संवेदनशील और जटिल है, कि कई समस्याएं हैं।

एकवचन और आकस्मिक, कि कानून अमूर्त प्रस्ताव नहीं हैं और अमूर्त इकाइयों से संबंधित नहीं हैं और इन्हें अमूर्त समरूपता द्वारा मापा नहीं जाना चाहिए; "कि सटीक ज्ञान और उपचार का अच्छा अनुकूलन हमेशा संभव नहीं होता है" और यह कि "निर्णय काफी हद तक अल्प और अप्रमाणित पर आधारित एक भविष्यवाणी है। अनुभव '। प्रत्येक विधान, विशेष रूप से आर्थिक मामलों में, अनिवार्य रूप से अनुभवजन्य है और

यह प्रयोग पर आधारित है या जिसे कोई परीक्षण और त्रुटि विधि कह सकता है और इसलिए यह सभी संभावित स्थितियों के लिए प्रदान नहीं कर सकता है या सभी संभावित दुरुपयोगों का अनुमान नहीं लगा सकता है। जटिल प्रयोगात्मक आर्थिक विधान में कठोरता और असमानताएँ हो सकती हैं, लेकिन केवल इसी कारण से इसे अमान्य नहीं माना जा सकता है। अदालतें

ऐसा नहीं किया जा सकता है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने सचिव में बताया है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कृषि बनाम। सेंट्रल रॉयंग रिफाइनिंग कंपनी को ऐसी खामियों और असमानताओं से राहत के लिए न्यायाधिकरणों में परिवर्तित किया जाए। दुरुपयोग की संभावनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन वह भी अपने आप में कानून को अमान्य करने का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी विधायिका के लिए यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि किसी दैवीय विवेक, विकृतियों और इसके विधान के दुरुपयोग से जो इसके प्रावधानों के अधीन लोगों द्वारा किया जा सकता है और इस तरह के विकृतियों और दुरुपयोग के खिलाफ प्रावधान किया जा सकता है। वास्तव में, इसके निर्माण पर कितना भी ध्यान दिया जाए, ऐसे कानून की कल्पना करना मुश्किल है जो विकृत मानव सरलता द्वारा दुरुपयोग किए जाने में सक्षम न हो। इसलिए न्यायालय को इस तरह की संवैधानिकता पर निर्णय लेना चाहिए। अपने प्रावधानों की व्यापकता से कानून बनाना, न कि अपनी खामियों या असमानताओं से या इसके किसी भी प्रावधान के दुरुपयोग की संभावनाओं से। यदि कोई क्रूरता, असमानताएँ या संभावनाएँ

दुरुपयोग सामने आता है, विधायिका हमेशा कदम उठा सकती है और उपयुक्त संशोधनकारी कानून बना सकती है। यही व्यावहारिक दृष्टिकोण का सार है जिसे जटिल आर्थिक मुद्दों से निपटने में विधायिका का मार्गदर्शन और प्रेरणा करनी चाहिए।

19. यह विचार करना न्यायालय के प्रांत के बाहर होगा कि क्या कोई विशेष छूट या छूट आवश्यक है या नहीं।

काले धन का खुलासा करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नहीं। यह व्यावहारिक आवश्यकता और 'प्रशासनिक समीचीनता' के आधार पर विविध राजकोषीय और आर्थिक विचारों पर निर्भर करेगा और इसमें एक निश्चित मात्रा में प्रयोग भी शामिल होंगे जिन पर निर्णय देने के लिए न्यायालय कम से कम उपयुक्त होगा। न्यायालय के पास ऐसे आर्थिक मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक क्षमता और विशेषज्ञता नहीं होगी। न्यायालय संभवतः यह आकलन या मूल्यांकन नहीं कर सकता है कि किसी विशेष प्रतिरक्षा का क्या प्रभाव होगा या

छूट और क्या यह उद्देश्य को पूरा करेगा या नहीं। वहाँ इतने सारे अभेद्य हैं जो प्रवेश करेंगे

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव मुन्न वी में। इलिनोइस, अर्थात्, कि अदालतें अपने ओ. एस. ई. आर. बेयर करमचारी यूनियन टी. एच. आर. को प्रतिस्थापित नहीं करती हैं।

राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनाम। भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

विधायी निर्णय के लिए सामाजिक और आर्थिक विश्वास

शरीर '। न्यायालय को सामाजिक और आर्थिक नीतियों से संबंधित मामलों में विधायी निर्णय को स्थगित करना चाहिए और हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि विधायी निर्णय का प्रयोग निम्नानुसार प्रतीत न हो।

स्पष्ट रूप से मनमाना। न्यायालय को लगातार खुद को याद दिलाना चाहिए कि

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने मेट्रोपोलिस थिएटर कंपनी बनाम में क्या कहा शिकागो शहर:

" 12. सरकार की समस्याएं व्यावहारिक हैं।

और उचित ठहरा सकते हैं, यदि उन्हें आवश्यकता नहीं है, तो मोटा-मोटी आवास, यह अतार्किक और अवैज्ञानिक हो सकता है। लेकिन

इस तरह की आलोचना भी जल्दबाजी में नहीं की जानी चाहिए। क्या? सबसे अच्छा हमेशा स्पष्ट नहीं होता है, किसी भी विकल्प का ज्ञान

विवादित या निंदा की जा सकती है। केवल सरकार की गलती

वे हमारी न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हैं।

यह सच है कि एक या दूसरी प्रतिरक्षाएं या

अधिनियम के प्रावधानों के तहत दी गई छूट का लाभ साधन संपन्न व्यक्तियों द्वारा कुशलता को अपनाकर उठाया जा सकता है।

कर से बचने या बचत करने की दृष्टि से तरीके और उपकरण। लेकिन इससे मदद नहीं मिल सकती क्योंकि जब कर से बचने की बात आती है तो मानव चतुराई इतनी अधिक होती है कि कर कानून बनाना लगभग असंभव होगा जिसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, परीक्षण और त्रुटि विधि प्रत्येक में निहित है

किसी जिद्दी सामाजिक या आर्थिक मुद्दे से निपटने के लिए विधायी प्रयास और यदि यह पाया जाता है कि अधिनियम के तहत दी गई किसी भी छूट या छूट का उपयोग कर चोरी या बचने के लिए किया जा रहा है जो विधायिका का इरादा नहीं है, तो अधिनियम में हमेशा संशोधन किया जा सकता है और दुरुपयोग को समाप्त किया जा सकता है। तदनुसार हमारा विचार है कि अधिनियम का कोई भी प्रावधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है और इसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

22. इसी तरह, भावेश डी. पैरिश बनाम। भारत संघ

(2000) 5 एस. सी. सी. 471, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 26. कुछ अनौपचारिक क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं

भारतीय अर्थव्यवस्था को कमतर नहीं आंका जा सका। हालांकि, इसमें

आर्थिक प्रगति का मार्ग, यदि अनौपचारिक प्रणाली की मांग की गई थी

एक अधिक संगठित प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना, बेहतर करने में सक्षम विनियमन और अनुशासन, तब यह एक आर्थिक दर्शन [2023] 6 एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विचाराधीन कानून द्वारा प्रतिबिंबित। ऐसा दर्शन हो सकता है इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। लेकिन ये थे मुद्दे

आर्थिक नीति। उन्हें सबसे अच्छा ज्ञान के लिए छोड़ दिया जाता है

विधायिका और नीतिगत मामलों में स्वीकृत सिद्धांत यह है कि अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा के संदर्भ में

लोगों की विशेषज्ञता ने आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया

विषय के साथ हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। द.

इस तरह के प्रतिबंध के परिणाम बड़े पैमाने पर हो सकते हैं

प्रभाव और घड़ी को कई वर्षों तक पीछे रख सकते हैं।

अर्थव्यवस्था में दुर्बलताओं को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया

इसे गंभीर खतरे में डाला जा सकता है और इसलिए, यह आवश्यक है

कि आर्थिक विधानों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय, जबकि

ऐसे मामले जहां कानून में परिलक्षित दृष्टिकोण संभव नहीं है किसी भी तरह से लिया जाना।

30. निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले एक और बात है जो हम

विवाद में, विधायी वसीयत को आम तौर पर इस तरह के विचार के लंबित रहने तक निलंबन के तहत नहीं रखा जाना चाहिए। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है, जब तक कि उसे अंतिम सुनवाई के बाद अलग नहीं कर दिया जाता है और इसलिए, अंतरिम स्तर पर आर्थिक सुधार से संबंधित कानून पर रोक लगाने की प्रवृत्ति को समझा नहीं जा सकता है। नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली का उपयोग संतुलित तरीके से किया जाना चाहिए जिसका प्राथमिक उद्देश्य है - इसकी संवैधानिक प्रभावकारिता पर संदेह करके इसके विकास को निलंबित करने के बजाय आर्थिक विकास में तेजी लाना।

(जोर दिया गया)

आई. ओ. एस. ई. आर. बेयर करमचारी यूनियन टी. एच. आर. राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनाम। भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

23. विदेश व्यापार महानिदेशालय बनाम। कनक एक्सपोर्ट्स, (2016) 2 एस. सी. सी. 226, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:

" 109. इसलिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार को किसी विशेष योजना में संशोधन, संशोधन या रद्द करने का अधिकार है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जटिल आर्थिक मामलों में प्रत्येक निर्णय अनिवार्य रूप से अनुभवजन्य होता है और यह प्रयोग पर आधारित होता है या जिसे कोई परीक्षण और त्रुटि विधि कह सकता है और इसलिए, इसकी वैधता का परीक्षण किसी भी कठोर पूर्व विचार या किसी भी स्ट्रेटजिक सूत्र के अनुप्रयोग पर नहीं किया जा सकता है। बाल्को कर्मचारी संघ बनाम। भारत संघ, (2002) 2 एस. सी. सी. 333], उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कार्यकारी कार्यवाई सहित कानूनों को

भाषण की स्वतंत्रता, धर्म आदि जैसे नागरिक अधिकारों को छूने वाले कानूनों की तुलना में अधिक अक्षांश के साथ देखा जाना चाहिए कि विधायिका को जोड़ों में कुछ खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि इससे निपटना पड़ता है

जटिल समस्याएं जो किसी भी माध्यम से समाधान को स्वीकार नहीं करती हैं

सिद्धांत या स्ट्रेटजिक सूत्र और यह विशेष रूप से आर्थिक मामलों से निपटने वाले कानून के मामले में सच है, जहां समस्याओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विधायिका को अधिक अक्षांश की अनुमति देने की आवश्यकता होती है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता का कारण

27. जैसा कि स्पष्ट है, प्रस्तावना इस बात की अंतर्दृष्टि देती है कि संहिता द्वारा क्या हासिल करने की कोशिश की जाती है। संहिता सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, कॉर्पोरेट देनदारों के पुनर्गठन और दिवालिया समाधान के लिए एक संहिता। जब तक इस तरह का पुनर्गठन समयबद्ध तरीके से नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति का मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए, ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना ताकि उन्हें कुशलता से चलाया जा सके।

संहिता का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य। यह बदले में उद्यमिता को बढ़ावा देगा क्योंकि निगमित देनदार के प्रबंधन में व्यक्तियों को हटा दिया जाता है और उद्यमियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। कब,

इसलिए, एक समाधान योजना शुरू होती है और कॉर्पोरेट देनदार को आर्थिक मुख्यधारा में वापस लाया जाता है, यह अपने ऋणों को चुकाने में सक्षम होता है, जो बदले में, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के हाथों में ऋण की व्यवहार्यता को बढ़ाता है। सबसे बढ़कर, अंत में, सभी हितधारकों के हितों की देखभाल कॉर्पोरेट देनदार [2023] 6 एस. सी. आर. के रूप में की जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्वयं समाधान योजना का लाभार्थी बन जाता है-श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, लंबे समय में लेनदारों को पूरा भुगतान किया जाएगा, और शेयरधारक/निवेशक अपने निवेश को अधिकतम करने में सक्षम होंगे। एक कॉर्पोरेट देनदार का समय पर समाधान, जो एक प्रभावी कानूनी ढांचे द्वारा संकट में है, ऋण बाजारों के विकास का समर्थन करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। चूंकि अर्थव्यवस्था में वापस आए धन से अधिक निवेश किया जा सकता है, इसलिए व्यापार तब आसान हो जाता है, जो कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च आर्थिक विकास और विकास की ओर ले जाता है। दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावना किसी भी तरह से इसका उल्लेख नहीं करती है

परिसमापन, जिसका लाभ केवल अंतिम उपाय के रूप में तब लिया जाता है जब या तो कोई समाधान योजना नहीं होती है या प्रस्तुत की गई समाधान योजनाएं सही नहीं होती हैं। परिसमापन में भी परिसमापक निगमित देनदार के व्यवसाय को चालू चिंता के रूप में बेच सकता है।

(आर्सेलर मित्तल (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम देखें। सतीश कुमार गुप्ता, (2019) 2 एस. सी. सी. 1 पैरा 83, एफ. एन. 3)।

उपसंहार

120. दिवाला संहिता एक ऐसा कानून है जो आर्थिक मामलों से संबंधित है और बड़े अर्थों में अर्थव्यवस्था से संबंधित है।

पूरे देश में। पहले के प्रयोग, जैसा कि हमने देखा है, विधानों के विफल होने के संदर्भ में, "परीक्षण" बार-बार "त्रुटियों" का कारण बना, अंततः संहिता के अधिनियमन का कारण बना। द. संहिता में निहित प्रयोग, जिसे इसके प्रावधानों की व्यापकता द्वारा आंका जाता है, न कि याचिकाकर्ताओं द्वारा बताई गई तथाकथित कुरूपताओं और असमानताओं द्वारा, संवैधानिक रूप से पारित किया जाता है। आर्थिक चीजों में प्रयोग जारी रखना एक गंभीर जिम्मेदारी है, और प्रयोग करने के अधिकार से इनकार करना गंभीर है।

राष्ट्र के लिए परिणाम। हमने यह भी देखा है कि काम

संहिता की निगरानी केंद्र सरकार द्वारा विशेषज्ञ समितियों द्वारा की जा रही है जो इस संबंध में स्थापित की गई हैं। जिस छोटी अवधि में संहिता संचालित हुई है, उसमें संहिता के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए अधीनस्थ विधान दोनों में संशोधन किए गए हैं। यह प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है जिसमें याचिकाकर्ताओं सहित सभी हितधारक शामिल हैं।

***** मोसर बेयर करमचारी यूनियन टीएचआर। राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनाम। भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

9. जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 दिवालियापन और दिवालियापन से संबंधित नहीं है जब कंपनियां भुगतान करने में असमर्थ होती हैं।

और संहिता के तहत परिकल्पित पुनरुद्धार और पुनर्वास योजना के लिए आधार। दोनों अधिनियम दो अलग-अलग स्थितियों से संबंधित हैं और हमारी राय में, जब हम जांच करते हैं कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भेदभाव या उल्लंघन है तो उनकी बराबरी नहीं की जा सकती है। कंपनियों के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए, श्रमिकों सहित सभी क्षेत्रों से कुछ त्याग की आवश्यकता होती है। दिवालिया कंपनियों के मामले में, अस्तित्व और पुनर्जनन के लिए, सुरक्षित लेनदारों और केंद्र और राज्य सरकार सहित सभी की आवश्यकता होती है। बलिदान करने के लिए। कंपनी के पुनरुद्धार से श्रमिकों की भी हिस्सेदारी और लाभ होता है, और इसलिए जब तक यह नहीं पाया जाता है कि

श्रमिकों के लिए परिकल्पित बलिदान, जो निश्चित रूप से एक अलग वर्ग बनाते हैं, भारी और बोझिल हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और मनमाना होने के कारण, हम कानून को केवल इस आधार पर दरकिनार नहीं करेंगे कि श्रमिकों द्वारा कुछ या मामूली बलिदान किया जाना है। हम इस तर्क को भी अस्वीकार करेंगे कि यह पता लगाने के लिए कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया था या क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया गया था, हमें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिकल्पित झरना तंत्र की मौखिक रूप से जांच करनी चाहिए, जहां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 271 के आधार (ए) से (ई) के संदर्भ में कंपनी को समाप्त कर दिया गया है; और जब दिवालिया कंपनी को संहिता के तहत पुनर्जीवित, पुनर्वासित या समाप्त करने की मांग की जाती है तो श्रमिकों के अधिकारों की। दोनों अधिनियमों के उद्देश्य और उद्देश्य के संदर्भ में आधार और परिस्थितियाँ पूरी तरह से अलग हैं।

10. अब हम झरने के तंत्र में अंतर की ओर मुड़ते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 और संहिता में प्रावधान किया गया है। धारा 3246 के अनुसार

6 324. सभी विवरणों के ऋणों को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रत्येक समापन में (दिवालिया कंपनियों के मामले में, [2023] 6 एस. सी. आर. के अनुसार आवेदन के अधीन।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7 326. तरजीही भुगतानों को ओवरराइड करना। (1) इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी के समापन में, निम्नलिखित ऋणों का भुगतान अन्य सभी ऋणों की तुलना में प्राथमिकता से किया जाएगा: ((क) कामगारों का बकाया; और (ख) जहां एक सुरक्षित लेनदार ने एक सुरक्षित संपत्ति का भुगतान किया है, ऐसे सुरक्षित लेनदार के बकाया ऋणों का इतना हिस्सा जो उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है या उसकी प्रतिभूति में श्रमिकों के हिस्से की राशि (यदि कानून के तहत देय हो), जो भी कम हो, श्रमिकों के बकाया के बराबर है:

बशर्ते कि किसी कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट राशियां, जो परिसमापन आदेश से पहले दो वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी अन्य अवधि के लिए देय हैं, जो निर्धारित की जाएं, परिसंपत्तियों की बिक्री के तीस दिनों की अवधि के भीतर अन्य सभी ऋणों (सुरक्षित लेनदारों को देय ऋणों सहित) के लिए प्राथमिकता से भुगतान की जाएंगी और सुरक्षित लेनदारों की प्रतिभूति पर ऐसे शुल्क के अधीन होंगी जो निर्धारित किया जाए।

(2) उप-धारा (1) के परंतुक के तहत देय ऋणों का भुगतान सुरक्षित लेनदारों को कोई भी भुगतान करने से पहले पूरा भुगतान किया जाएगा और उसके बाद उस उप-धारा के तहत देय ऋणों का पूरा भुगतान किया जाएगा, जब तक कि संपत्ति उन्हें पूरा करने के लिए अपर्याप्त न हो, उस स्थिति में वे समान अनुपात में कम हो जाएंगे।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, और किसी कंपनी के संबंध में धारा 327 (ए) "कर्मचारी" का अर्थ है कंपनी के कर्मचारी, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (ओं) के अर्थ के भीतर कर्मचारी हैं;

(ख) किसी कंपनी के संबंध में "श्रमिकों के देय" का अर्थ है कंपनी से उसके श्रमिकों को देय निम्नलिखित राशियों का कुल योग, अर्थात्

((i) सेवाओं के संबंध में किसी भी कर्मचारी के कमीशन के माध्यम से पूरी तरह से या आंशिक रूप से अर्जित समय या टुकड़ों के काम के लिए देय मजदूरी और वेतन सहित सभी मजदूरी या वेतन।

कंपनी को प्रदान किया गया और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी कर्मचारी को देय कोई भी मुआवजा;

((ख) समापन आदेश या संकल्प से पहले या उसके प्रभाव से किसी भी कर्मचारी को या उसकी मृत्यु की स्थिति में, उसके अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति को उसके रोजगार की समाप्ति पर देय होने वाला सभी उपार्जित अवकाश पारिश्रमिक;

(iii) जब तक कि कंपनी को केवल किसी अन्य कंपनी के साथ पुनर्निर्माण या एकीकरण के उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से समाप्त नहीं किया जा रहा है या जब तक कि कंपनी को समाप्त होने की शुरुआत में, बीमाकर्ताओं के साथ ऐसे अनुबंध के तहत, जैसा कि श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 14 में उल्लिखित है, मोसर बेयर कर्मचारी संघ होने में सक्षम अधिकार नहीं हैं।

राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनाम। भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

कंपनी अधिनियम, 2013 अधिमाम्य भुगतानों से संबंधित है जिनका भुगतान अन्य सभी ऋणों की तुलना में प्राथमिकता से किया जाना है। इनमें श्रमिकों के ऋण और सुरक्षित लेनदार का बकाया शामिल है जहां सुरक्षित लेनदार को सुरक्षित संपत्ति का एहसास हो गया है, लेकिन वह पूरी राशि का भुगतान नहीं कर सका है, या कानून के तहत देय अपनी प्रतिभूति में श्रमिकों के हिस्से की राशि, जो भी कम हो, श्रमिकों के बकाया के बराबर है। इस प्रकार, यह सुरक्षित परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए सुरक्षित लेनदार के अधिकारों को संतुलित और समान करता है, लेकिन यदि सुरक्षित लेनदार पूरी राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं है या कानून के तहत देय होने पर श्रमिकों को एक राशि का भुगतान किया है, जो भी कम हो, तो ये बकाया श्रमिकों के बकाया के बराबर है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 का स्पष्टीकरण 'कामगार' को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (ओं) के अर्थ के भीतर कर्मचारी; और 'कामगारों का बकाया' और 'कामगारों का हिस्सा', जो अभिव्यक्तियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की शर्तें हैं जो विशेष रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में उपयोग की जाती हैं। श्रमिकों का हिस्सा

कम्पनीक कोनो सुरक्षित लेनदारक प्रतिभूतिक सम्बन्धसँ अभिप्रेत अछि -

जो राशि प्रतिभूति के मूल्य के बराबर होती है, उसी अनुपात में जो श्रमिकों के बकाया की राशि श्रमिकों के बकाया की राशि और सुरक्षित लेनदारों को देय ऋणों की राशि के कुल के बराबर होती है। चित्रण एक काल्पनिक मामले के माध्यम से सूत्र को स्पष्ट करता है, जहां सुरक्षित लेनदारों और श्रमिकों दोनों का बकाया 1 लाख रुपये है। कंपनी से सुरक्षित लेनदारों को देय ऋण की राशि को अनुमानित रूप से रु। 3 एक लाख। तदनुसार, कुल राशि

कंपनी के किसी भी कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए किसी भी मुआवजे या दायित्व के संबंध में देय सारी राशि कामगारों को हस्तांतरित और निहित की गई; ((iv) भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य कोष से किसी भी कर्मचारी को देय सभी राशि;

(ग) किसी कंपनी के किसी भी सुरक्षित लेनदार की प्रतिभूति के संबंध में "श्रमिकों के हिस्से" का अर्थ है वह राशि जो प्रतिभूति के मूल्य के बराबर है जो श्रमिकों के बकाया की राशि के बराबर है जो श्रमिकों के बकाया की राशि और सुरक्षित लेनदारों को देय ऋणों की राशि के कुल अनुपात के बराबर है।

चित्रण

एक कंपनी के सुरक्षित लेनदार की प्रतिभूति का मूल्य रु। 1,00,000 . श्रमिकों की बकाया राशि की कुल राशि रु। 1,00,000 . कंपनी से उसके सुरक्षित लेनदारों को देय ऋण की राशि रु। 3,00,000 . श्रमिकों के बकाया और सुरक्षित लेनदारों के बकाया ऋणों की कुल राशि रु। 4,00,000 . इसलिए श्रमिकों का प्रतिभूति का हिस्सा प्रतिभूति के मूल्य का एक-चौथाई है, जो कि रु। 25,000 .

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्रमिकों के बकाया और सुरक्षित लेनदारों के बकाया ऋण की राशि रु। 4 एक लाख। इस पृष्ठभूमि में, जब सुरक्षित लेनदारों की प्रतिभूति का मूल्य रु। 1 एक लाख, प्रतिभूति के मूल्य का एक-चौथाई, यानी रु। 25,000 / - यह श्रमिकों का हिस्सा होगा। इस हद तक कोई कठिनाई या विवाद नहीं है। जैसा कि नीचे देखा गया है कि शायद ही कोई

संहिता के तहत उक्त पदानुक्रम और झरना तंत्र में अंतर।

11. हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 की उप-धारा (1) के प्रावधान में कहा गया है कि कंपनी को बंद करने की स्थिति में,

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 के स्पष्टीकरण के उपखंड (i) और (ii) से खंड (ख) में निर्दिष्ट राशियाँ, जो हैं - परिसमापन आदेश से पहले दो साल की अवधि के लिए देय या ऐसी अन्य अवधि जो निर्धारित की जाए, का भुगतान अन्य सभी ऋणों के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सुरक्षित लेनदारों को देय ऋण भी शामिल हैं। यह भुगतान परिसंपत्तियों की बिक्री से तीस दिनों की अवधि के भीतर किया जाना है और सुरक्षित लेनदारों की प्रतिभूति पर इस तरह के शुल्क के अधीन होगा। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 के स्पष्टीकरण के उपखंड (i) से खंड (b) तक सभी मजदूरी या वेतन को संदर्भित करता है, जिसमें मजदूरी भी शामिल है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के किसी भी प्रावधान के तहत पूरी तरह से या आंशिक रूप से अर्जित समय या टुकड़ों में काम और वेतन आदि के लिए देय। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 के स्पष्टीकरण के खंड (बी) के उपखंड (ii) में किसी भी कर्मचारी को या उसकी मृत्यु की स्थिति में, किसी अन्य व्यक्ति को उसके अधिकार में देय सभी उपार्जित अवकाश पारिश्रमिक के बारे में बताया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 के स्पष्टीकरण के खंड (बी) के उपखंड (iii) और (iv) को बाहर रखा गया है।

प्रावधान से। ये उपखंड श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत श्रमिकों की मृत्यु या अक्षमता के संबंध में मुआवजे के दायित्व या भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान निधि या श्रमिकों के कल्याण के किसी अन्य कोष से किसी भी श्रमिक को देय सभी राशियों से संबंधित हैं। इस प्रावधान से जो बात स्पष्ट है वह यह है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 के स्पष्टीकरण के खंड (बी) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट राशियों के लिए किसी कंपनी को बंद करने के मामले में परंतुक लागू होता है जो एक अवधि के लिए देय होती हैं।

8 वर्तमान निर्णय के उद्देश्य के लिए, हमें कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 1956 या संहिता की धारा 36 (4) (ए) (iii) के तहत श्रमिकों के बकाया के भुगतान पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, देखें-कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त बनाम। एस्के फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के आधिकारिक परिसमापक, (2011) 10 एस. सी. सी. 727 और भूपिंदर सिंह बनाम। यूनिटेक लिमिटेड, (2022) 8 एससीसी 749।

मोसर बेयर करमचारी यूनियन टीएचआर। राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनामा भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

समापन आदेश से दो साल पहले या ऐसी अन्य अवधि के रूप में

निर्धारित किया जा सकता है। हमें सूचित नहीं किया जाता है कि एक अलग अवधि निर्धारित की गई है और इसलिए, कंपनी अधिनियम की धारा 326 के स्पष्टीकरण के उपखंड (i) और (ii) से खंड (b) में निर्दिष्ट राशियाँ, 2013 समापन आदेश से पहले दो वर्षों के लिए देय हैं। इस प्रकार, दो वर्ष की यह अवधि समापन आदेश की तारीख के संदर्भ में है, न कि समय के संदर्भ में पहले की तारीख के संदर्भ में, जब एक समापन याचिका दायर की जाती है। यह उस अवधि को प्रतिबंधित करता है जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 के स्पष्टीकरण के उपखंड (i) और (ii) से खंड (b) के तहत भुगतान लागू होगा। पूरा भुगतान नहीं किया गया

बकाया राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 की उप-धारा (1) के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आती है।

12. जब हम संहिता की ओर ध्यान देते हैं, तो सबसे पहले इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए

कि संहिता की धारा 36 (4) (ए) (iii) के संदर्भ में, भविष्य निधि, पेंशन निधि और उपदान निधि से किसी भी कर्मचारी या कर्मचारी को देय सभी राशियाँ हिस्सा नहीं हैं और उन्हें परिसमापन कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाना है। संहिता की धारा 52 की उप-धारा (1) एक सुरक्षित लेनदार को दो विकल्प देती है। सबसे पहले, परिसमापन कार्यवाही में सुरक्षित लेनदार अपने प्रतिभूति ब्याज को छोड़ सकता है और उससे आय प्राप्त कर सकता है

परिसमापक द्वारा संहिता की धारा 53 में निर्दिष्ट तरीके से परिसंपत्तियों की बिक्री। दूसरा विकल्प सुरक्षा हित का एहसास करना है, लेकिन संहिता की धारा 52 में निर्दिष्ट तरीके से। संहिता की धारा 52 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि जहां सुरक्षित लेनदार को प्रतिभूति हित का एहसास होता है, वह परिसमापक को ऐसे प्रतिभूति हित के बारे में सूचित करेगा और ऐसे प्रतिभूति हित की प्राप्ति के अधीन संपत्ति की पहचान करेगा। परिसमापक को प्रतिभूति ब्याज का सत्यापन करना होता है और वह प्रतिभूति लेनदार को ऐसे प्रतिभूति हित का एहसास करने की अनुमति देगा, जो या तो किसी सूचना उपयोगिता द्वारा बनाए गए ऐसे प्रतिभूति हित के रिकॉर्ड से या ऐसे अन्य द्वारा साबित होता है।

इसका अर्थ बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। संहिता की धारा 52 की उप-धारा (4) में कहा गया है कि सुरक्षित लेनदार ऐसे कानून के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को लागू कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, निपट सकता है, समझौता कर सकता है या उसके साथ सौदा कर सकता है।

जैसा कि प्राप्त किए जा रहे प्रतिभूति ब्याज और प्रतिभूत लेनदार पर लागू होता है। सुरक्षित लेनदार को तदनुसार आय को लागू करना है

9 वर्तमान निर्णय के प्रयोजन के लिए, हम संहिता की धारा 36 की उप-धारा (4) के खंड (ए) के उप-खंड (iii) की व्याख्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह कुछ बहस का मुद्दा है और अन्य मामलों में विचाराधीन है। बहिष्करण का कानूनी प्रभाव यह है कि, भविष्य निधि, पेंशन निधि या उपदान निधि से किसी भी कर्मचारी या कर्मचारी को देय राशि को पुनर्वास या पुनरुद्धार योजना में भी कटौती या कमजोर करने का विषय नहीं बनाया जा सकता है। उन्हें झरना तंत्र से बाहर रखा गया है और परिसमापन पर पुनर्प्राप्ति में उपयोग नहीं किया जाएगा, और उन्हें साझा नहीं किया जा सकता है।

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसके देय ऋण की वसूली करें। हमें संहिता की धारा 52 की उप-धारा (5) का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह उस कार्रवाई से संबंधित है जो प्रतिभूत लेनदार कर सकता है यदि वह निगमित देनदार से प्रतिरोध का सामना करता है या

कब्जा लेने, बेचने या बेचने में उससे जुड़ा कोई अन्य व्यक्ति

सुरक्षित लेनदार को देय ऋणों की अधिकता, सुरक्षित लेनदार ऐसी सुरक्षित परिसंपत्तियों के प्रवर्तन से परिसमापक को अतिरिक्त/अधिशेष राशि का लेखा देगा और भुगतान करेगा। दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों की राशि, जो सुरक्षित लेनदारों से देय है जो अपने ऋण का भुगतान करते हैं। इस धारा में दिए गए तरीके से प्रतिभूति हितों की कटौती ऐसे प्रतिभूत लेनदारों द्वारा किसी भी वसूली की आय से की जानी है। वे.

हस्तांतरण किया जाना है और परिसमापन संपत्ति में शामिल किया जाना है। संहिता की धारा 52 की उप-धारा (9) में कहा गया है कि जहां प्रतिभूत परिसंपत्तियों की वसूली के लिए आय प्रतिभूत लेनदार को देय ऋणों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसे प्रतिभूत लेनदार के अवैतनिक ऋणों का भुगतान परिसमापक द्वारा संहिता की धारा 53 के खंड (ई) से उप-धारा (1) में निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

13. श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए जहां सुरक्षित

प्रतिभूति ब्याज को परिसमापन संपदा का हिस्सा माना जाएगा। (2) जहां कोई प्रतिभूति प्राप्त लेनदार अपने प्रतिभूति ब्याज को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, वह-(ए) धारा 53 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और खंड (बी) के उप-खंड (आई) के तहत देय राशि के लिए उतना ही भुगतान करेगा, जितना कि उसने धारा 53 को छोड़ने की स्थिति में साझा किया होगा। परिसमापन शुरू होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर परिसमापक को प्रतिभूति ब्याज; और

(ख) परिसमापन शुरू होने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर परिसमापक को संपत्ति के प्राप्त मूल्य की अधिकता, जो प्रतिभूति ब्याज के अधीन है, उसके स्वीकार किए गए दावों की राशि से अधिक है: बशर्ते कि जहां इस उप-विनियम के तहत देय राशि इस उप-विनियम के तहत देय राशि की तारीख तक निश्चित नहीं है, तो सुरक्षित लेनदार परिसमापक द्वारा अनुमानित राशि का भुगतान करेगा:

मोसर बेयर करमचारी यूनियन टीएचआर। राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनामा भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

भारत सरकार (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 अधिनियमित किया गया है, और यह आवश्यक है कि सुरक्षित लेनदार, जो संहिता की धारा 52 के अनुसार अपने प्रतिभूति ब्याज का एहसास करने का विकल्प चुनता है, को संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और उप-खंड (आई) से खंड (बी) के तहत देय राशि का भुगतान समय और उसमें निर्धारित तरीके के भीतर परिसमापक को करना होगा। कामगारों का बकाया, तब भी जब सुरक्षित लेनदार संहिता की धारा 52 के तहत आगे बढ़ने का विकल्प चुनता है, इसलिए संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) के उप-खंड (बी) के संदर्भ में संरक्षित है।

14. संहिता की धारा 53 का उल्लेख करने से पहले, हम संहिता की धारा 30 पर ध्यान देना चाहेंगे, जो इसे प्रस्तुत करने से संबंधित है। समाधान योजना, जिसकी समाधान पेशेवर द्वारा धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्धारित तरीके से जांच की जानी आवश्यक है।

बशर्ते कि इस उप-विनियम के तहत देय राशि और पहले परंतुक के तहत भुगतान की गई राशि के बीच कोई अंतर सुरक्षित लेनदार या परिसमापक द्वारा, जैसा भी मामला हो, इस उप-विनियम के तहत देय राशि निश्चित होते ही ठीक कर दिया जाएगा और परिसमापक द्वारा सूचित किया जाएगा। (3) यदि कोई प्रतिभूत लेनदार उप-विनियम (2) का पालन करने में विफल रहता है, तो परिसंपत्ति, जो प्रतिभूति ब्याज के अधीन है, परिसमापन संपदा का हिस्सा बन जाएगा।

1 1 30. समाधान योजना प्रस्तुत करना। - (1) एक समाधान आवेदक एक हलफनामे के साथ एक समाधान योजना प्रस्तुत कर सकता है जिसमें कहा गया है कि वह सूचना जापन के आधार पर तैयार किए गए समाधान पेशेवर को धारा 29-ए के तहत पात्र है। (2) समाधान पेशेवर अपने द्वारा प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की जांच करेगा ताकि यह पुष्टि की जा सके कि प्रत्येक समाधान योजना (क) निगमित देनदार के अन्य ऋणों के भुगतान को प्राथमिकता देते हुए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों के भुगतान का प्रावधान करता है;

(ख) परिचालन ऋणदाताओं के ऋणों का भुगतान बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से करने का प्रावधान है जो इससे कम नहीं होगा।

(i) धारा 53 के तहत निगमित देनदार के परिसमापन की स्थिति में ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि; या

योजना, ऐसी रीति से जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाए, जो निगमित देनदार के परिसमापन की स्थिति में धारा 53 की उप-धारा (1) के अनुसार ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगी। स्पष्टीकरण 1. — संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के प्रावधानों के अनुसार वितरण ऐसे लेनदारों के लिए उचित और न्यायसंगत होगा। स्पष्टीकरण 2. - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से इस खंड के प्रावधान एक निगमित देनदार [2023] 6 एस. सी. आर. की निगमित दिवालियापन समाधान प्रक्रिया पर भी लागू होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऋणी। संहिता की धारा 30 की उप-धारा (4) में कहा गया है कि ऋणदाताओं की समिति को समाधान योजना को कब और कैसे मंजूरी देनी है। उप-धारा (6) में कहा गया है कि समाधान पेशेवर ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। संहिता की धारा 31 1 2 समाधान योजना के अनुमोदन से संबंधित है। द. (i) जहाँ किसी समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित या अस्वीकार नहीं किया गया है;

(ii) जहाँ धारा 61 या धारा 62 के तहत अपील की गई है या ऐसी अपील पर उस समय लागू कानून के किसी प्रावधान के तहत समय की पाबंदी नहीं है; या (ग) जहाँ किसी समाधान योजना के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है;

(ग) समाधान योजना के अनुमोदन के बाद निगमित देनदार के मामलों के प्रबंधन का प्रावधान करता है;

(घ) समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण;

(ई) उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है; (च) ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

स्पष्टीकरण। खंड (ई) के प्रयोजनों के लिए, यदि समाधान योजना के तहत कार्यों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या किसी अन्य कानून के तहत शेयरधारकों की किसी भी मंजूरी की आवश्यकता है, तो ऐसी मंजूरी -

और इसके कर्मचारी, सदस्य, लेनदार, जिनमें केंद्र सरकार, कोई भी राज्य सरकार या कोई भी स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं, जिन्हें किसी भी कानून के तहत उत्पन्न बकाया के भुगतान के संबंध में ऋण दिया गया है, जैसे कि ऐसे अधिकारी जिन्हें वैधानिक बकाया है, गारंटर और समाधान योजना में शामिल अन्य हितधारक: बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, इस उप-धारा के तहत समाधान योजना के अनुमोदन के लिए एक आदेश पारित करने से पहले, यह संतुष्ट करेगा कि समाधान योजना में इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रावधान हैं। (2) जहाँ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि समाधान योजना

उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पुष्टि नहीं करती है, वह एक आदेश द्वारा समाधान योजना को अस्वीकार कर सकता है।

**** मोसर बेयर करमचारी यूनियन टीएचआर। राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनाम। भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को यह संतुष्ट करना है कि संहिता की धारा 30 की उप-धारा (4) के तहत लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना संहिता की धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसके अलावा, समाधान योजना में इसके प्रभावी कार्यान्वयन के प्रावधान हैं। संहिता की धारा 31 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी संतुष्ट है कि समाधान योजना संहिता की धारा 31 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पुष्टि नहीं करती है, तो वह एक आदेश द्वारा समाधान योजना को अस्वीकार कर सकता है। हमें संहिता की धारा 31 की अन्य उप-धाराओं का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

15. अब हम संहिता की धारा 53 की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होती है और कहती है कि इसके बावजूद

संसद द्वारा अधिनियमित किसी कानून में इसके विपरीत कुछ भी

यह है कि यह सुरक्षित लेनदार सहित पक्षों के अधिकारों को ओवरराइड करेगा, जब उक्त प्रावधान लागू होता है। संहिता की धारा 53 पूर्ण और व्यापक संहिता है जो परिसंपत्तियों का संग्रह सुनिश्चित करती है और फिर लेनदारों को भुगतान करने का तरीका प्रदान करती है। यहां तक कि सुरक्षा हित पर लागू होने वाली सुरक्षित परिसंपत्तियों को लागू करने, प्राप्त करने, निपटाने, समझौता करने या उनसे निपटने के लिए संहिता की धारा 53 के तहत आने वाले सुरक्षित लेनदार के अधिकारों को भी कम किया जाता है और उनसे समझौता किया जाता है।

15.1 धारा 53 की उप-धारा (1) का खंड (ए) दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों और परिसमापन लागतों से संबंधित है जो हैं -

पूरा भुगतान करना। इस संबंध में कोई शिकायत या मुद्दा नहीं उठाया जा सकता है खंड ने कहा। धारा 53 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में कहा गया है कि चौबीस की अवधि के लिए श्रमिकों के बकाया के रूप में देय ऋण

परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले के महीनों में और ऐसे सुरक्षित लेनदार द्वारा संहिता की धारा 52 में निर्धारित तरीके से प्रतिभूति छोड़ने की स्थिति में सुरक्षित लेनदार को देय ऋण श्रमिकों और सुरक्षित लेनदारों के बीच और उनके बीच समान रूप से रैंक करेंगे। द. संहिता की धारा 53 के स्पष्टीकरण

में कहा गया है कि 'श्रमिकों के बकाया' का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 में दिया गया है। दूसरे शब्दों में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 का स्पष्टीकरण शामिल किया गया है और संहिता की धारा 53 के खंड (बी) से उप-धारा (1) में निर्धारित झरने तंत्र पर लागू होता है। यहाँ जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि खंड (बी) से उप [2023] 6 एस. सी. आर. के तहत।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संहिता की धारा 53 की धारा (1) के अनुसार, श्रमिकों का बकाया परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले चौबीस महीने की अवधि के लिए है। परिसमापन प्रारंभ तिथि, जैसा कि उप के संदर्भ में परिभाषित किया गया है

संहिता की धारा 5 की धारा (17) समय की दृष्टि से बहुत पहले की है और समाप्त होने की तारीख के साथ मेल नहीं खाती है। यह श्रमिकों के हित में है। संहिता की धारा 53 के स्पष्टीकरण के खंड (i) में कहा गया है कि जहां प्राप्तकर्ताओं के वर्ग के संबंध में आय का वितरण किया जाता है

समान रूप से, प्रत्येक ऋण का भुगतान या तो पूर्ण रूप से किया जाएगा या प्राप्तकर्ताओं के समान वर्ग के भीतर समान अनुपात में भुगतान किया जाएगा, यदि

आय ऋणों को पूरी तरह से पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। प्रत्यक्षतः, खंड बहुत न्यायसंगत और निष्पक्ष है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि श्रमिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों को देय मजदूरी और अवैतनिक बकाया खंड (सी) में आता है, जो संहिता की धारा 53 के खंड (बी) से उप-धारा (1) के नीचे है। उन्हें केवल परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले बारह महीने की अवधि के लिए मजदूरी और अवैतनिक बकाया का भुगतान किया जाना है, और वह भी केवल तभी जब उपखंड (ए) और (बी) के संदर्भ में भुगतान करने के बाद अधिशेष निधि उपलब्ध हो।

संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1)। संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) का खंड (डी) असुरक्षित लोगों के वित्तीय ऋणों से संबंधित है।

लेनदार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार आदि को देय राशियों और प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन के बाद किसी भी राशि के लिए एक सुरक्षित लेनदार को देय ऋण को संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) के खंड (ई) में एक साथ जोड़ा गया है और उन्हें दोनों के बीच और उनके बीच समान रूप से क्रमबद्ध किया जाना है। शेष ऋण और बकाया संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) के खंड (च) में आते हैं। वरीयता शेयरधारक संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) के खंड (जी) के तहत आते हैं और इक्विटी शेयरधारक या भागीदार संहिता की धारा 53 की उप-धारा (1) के खंड (एच) के तहत आते हैं। संहिता की धारा 53 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि उप-धारा (1) के तहत प्राप्तकर्ताओं के बीच समान श्रेणी के साथ कोई भी संविदात्मक व्यवस्था, यदि उक्त उप-धारा के तहत प्राथमिकता के क्रम को बाधित करती है।

परिसमापक द्वारा अवहेलना की जाएगी।

16. झरना तंत्र एक संरचित प्रणाली पर आधारित है

गणितीय सूत्र, और पदानुक्रम कई योग्यताओं के साथ प्राथमिकता के क्रम में ऋणों के भुगतान के संदर्भ में बनाया गया है, किसी भी प्रावधान को समाप्त करना या झरने में पदानुक्रम को पुनर्व्यवस्थित करना।

तंत्र कई यात्राओं का कारण बन सकता है और समग्र और ठहराव के रूप में संतुलन के काम को बाधित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अस्थिरता हो सकती है। जलप्रपात तंत्र में हर बदलाव से सुरक्षित ऋणदाताओं के अधिकारों और हितों के संतुलन पर व्यापक प्रभाव पड़ना तय है।

राष्ट्रपति महेश चंद शर्मा बनाम। भारत संघ [एम. आर. शाह, जे.]

लेनदार और यहाँ तक कि केंद्र और राज्य सरकारें भी। के आधार पर

तथ्यों के अनुसार, कुछ मामलों में, संहिता में जलप्रपात तंत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 के तहत प्रदान किए गए पदानुक्रम की तुलना में अधिक फायदेमंद हो सकता है और इसके विपरीत। इसलिए हम संकोच करते हैं और याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार नहीं करते हैं। 17. यह संहिता कानून के जैविक विकास पर आधारित है और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया का एक उत्पाद है

परिसमापन को नियंत्रित करने वाली संहिता। इसने सभी व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने और हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए एक व्यापक और समयबद्ध ढांचा पेश किया। परिसमापन में भुगतान की प्राथमिकता निर्धारित करने में संहिता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत भारत में प्रथाओं को वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप लाना था। जलप्रपात तंत्र में, दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत के बाद और

परिसमापन, सुरक्षित लेनदार श्रमिकों के बकाया की एक निर्धारित अवधि के साथ उच्चतम प्राथमिकता साझा करते हैं। संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और संहिता की धारा 53 द्वारा निर्धारित झरना तंत्र के संदर्भ में श्रमिकों के अवैतनिक बकाया को पर्याप्त और महत्वपूर्ण रूप से संरक्षित किया जाता है। सुरक्षित लेनदार द्वारा प्रतिभूति को छोड़ने या न छोड़ने के किसी भी मामले में, श्रमिकों के हितों को संहिता के तहत संरक्षित किया जाता है। वास्तव में, सुरक्षित लेनदार बड़े पैमाने पर ऋण ले रहे हैं और कर्मचारियों को संहिता की धारा 53 के अनुसार न्यायसंगत और उचित तरीके से न्यायसंगत आधार पर मुआवजा दिया जा रहा है। यह संहिता सुरक्षित लेनदारों के अधिकारों को संतुलित करती है, जो वित्तीय संस्थान हैं जिनमें आम जनता ने धन का निवेश किया है, और यह भी सुनिश्चित करती है कि आर्थिक गतिविधि और एक व्यवहार्य कंपनी का पुनरुद्धार हो।

बाधित नहीं किया जाता है क्योंकि यह वित्तीय संकट का सामना कर चुका है या गिर गया है। संहिता दक्षता वृद्धि और परिणामस्वरूप अधिक से अधिक मूल्य प्राप्ति के माध्यम से अर्थव्यवस्था और राजकोष दोनों में अतिरिक्त लाभ लाने पर केंद्रित है। आर्थिक मामलों में, कानून निर्माता को एक व्यापक अक्षांश दिया जाता है और न्यायालय व्यावहारिक अनुभवों और कानून निर्माताओं द्वारा देखी गई अन्य समस्याओं के आधार पर ऐसे विधानों में प्रयोग करने की अनुमति देता है। इस तरह के कानून को चुनौती देते हुए, न्यायालय एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण नहीं अपनाता है। कुछ बलिदान हमेशा अधिक से अधिक भलाई के लिए किए जाने चाहिए, और जब तक कि ऐसे बलिदान प्रथम दृष्टया स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से कठोर न हों।

और स्पष्ट रूप से मनमाने के रूप में वर्गीकृत करने के लिए असमान, इनमें अदालत द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा। 18. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए और अधिनियम, 2013 की धारा 327 की उप-धारा (7) के रूप में यह प्रावधान है कि धारा [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

326 और अधिनियम, 2013 का 327 आई. बी. सी. के तहत परिसमापन की स्थिति में लागू नहीं होगा, जो आई. बी. सी. के अधिनियमन को देखते हुए आवश्यक हो गया है और यह आई. बी. सी. के परिसमापन के संबंध में लागू होता है

आई. बी. सी. के तहत कंपनी, अधिनियम, 2013 की धारा 327 (7) नहीं कहा जा सकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का मनमाना और/या उल्लंघनकारी होना। आई. बी. सी. के तहत किसी कंपनी के परिसमापन के मामले में, आई. बी. सी. के तहत कंपनी के परिसमापन के मामले में, आई. बी. सी. की धारा 36 (4) के अधीन आई. बी. सी. की धारा 53 के अनुसार परिसंपत्तियों का वितरण करना होगा। 19. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिकाओं में गुणों की कमी है और वे खारिज किए जाने के योग्य हैं और तदनुसार खारिज कर दिए जाते हैं। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

लिखित

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन

(सहायक: मयंक बत्रा, एलसीआरए)